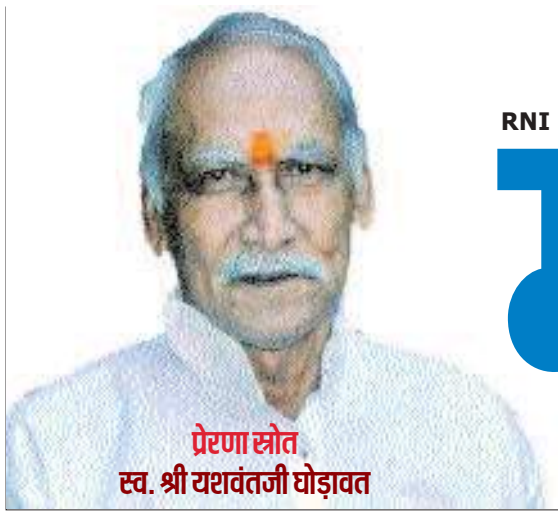

प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ.. सच

Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ़ कर देती है।
-महात्मा गांधी

वर्ष-02, अंक-43 (साप्ताहिक) खवासा, गुरुवार 30 जुलाई 2020 पृष्ठ-8, मूल्य-5 रुपए

कोरोना को लेकर क्या यही है प्रशासनिक व्यवस्था ?

माही की गूंज झाबुआ

कोरोना संक्रमण पर तब ही नियंत्रण पूर्णतः रूप से किया जा सकता है, जब आम लोग इस बीमारी की गंभीरता को समझ शासन के बनाए निर्देशों का पालन करें तो, वहीं प्रशासन के सामने तनीक भी कोरोना सिम्टम्स दिखे या सिम्टम्स की सूचना भी मिले तो प्रशासन 24 घंटे बिना किसी लापरवाही के अलर्ट रहकर अपना-अपना कार्य करेगा तो ही इस विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण से निजात मिल पाएगी अन्यथा नहीं।

गूंज निष्पक्षता के साथ जब-जब, जहां-जहां की जानकारी मिली कि, कोरोना संक्रमण को निजात दिलाने के लिए जिस व्यक्ति ने या जिस प्रशासनिक कर्मचारी व अधिकारी ने जहां उत्तम कार्य किया उनकी सराहना भी की है, परंतु जहां अनियमितताएं हुई उसे भी उजागर हमारी कलम के माध्यम से किया है।

आज हम ''कोरोना को लेकर क्या यही है प्रशासनिक व्यवस्था'' के प्रश्न के साथ वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थाओ के साथ जिस तरह से जिस जवाबदेही के साथ कार्य किया जा रहा है जिससे क्या कोरोना संक्रमण से जल्द निजात पा सकते हैं ? तो हर किसी का जवाब मिलेगा नहीं। 23 जुलाई को जिले के पेटलावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक 12 वर्षीय बालक को जिसका स्वास्थ्य करीब 2 माह से खराब चल रहा था जिसे उसकी मां व बड़ा भाई उपचार हेतु लेकर आए, डॉक्टरों ने तत्काल बालक को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर ऑक्सीजन लगाकर उपचार शुरू कर दिया। पूरी जांच के बाद डॉक्टर टीम को बालक में कोरोना जैसे सिम्टम्स लगे, जिस पर उपचार एवं कोरोना सैंपल लेने हेतु झाबुआ रेफर करने का निर्णय लिया गया, तथा बीमार बालक की मॉ को भी बताया कि कोरोना जैसे लक्षण बच्चे में दिख रहे हैं जिसके लिए झाबुआ रेफर कर रहे हैं, एंबुलेंस आ रही है जिसमें झाबुआ जाना है। महिला ने डॉक्टर को कुछ नहीं कहा पर महिला के मन में न जाने ऐसा क्या आया कि वह अपने बीमार पुत्र को लेकर इमरजेंसी वार्ड से चकमा देकर फरार हो गई। तत्पश्चात बीमार बालक लक्ष्मण पिता रामचंद्र मालीवार थांदला ब्लाक के नौगांवा कालिया का होने से, थांदला ब्लॉक के बीएमओ को सूचना देकर पेटलाद के स्वास्थ्य अमले ने अपने कार्य की इतिश्री कर दी। इसी तरह थांदला बीएमओ ने खवासा पुलिस चौकी पर सूचना देकर अपनी जवाबदेही की इतिश्री कर दी। खवासा पुलिस ने चौकी पर से ही बैठे-बैठे वहां के सरपंच से जानकारी लेकर अपने कार्य की इतिश्री कर दी। सरपंच ने पुलिस को थोड़ी-थोड़ी देर में जानकारी निकाल कर बताया कि, उसकी मां तोला अपने बड़े पुत्र हलिया के साथ बीमार लड़के को लेकर घर पहुंच गई है, तो पुलिस को 4 बजे लड़के की मौत हो जाने की सूचना मिल गई, शाम 6 बजे अंतिम संस्कार की सूचना भी पुलिस को सरपंच ने दे दी। खवासा पुलिस ने भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग को भी, जिस बीमार बालक को पेटलावद स्वास्थ्य विभाग कोरोना जैसे सिम्टम्स दिखने पर सैंपल एवं उपचार हेतु झाबुआ रेफर किया जा रहा था वही उसकी मॉ बिमार पुत्र को लेकर रफुच्चक्कर हो गई, पेटलावद बीएमओ चोपड़ा ने गूंज को पुष्टि भी कर दी थी कि, अगर बच्चे को उपचार नहीं मिला तो वह नहीं बचेगा। उक्त बीमार बालक की पेटलावद चिकित्सालय से उसकी मां द्वारा ही ले जाने के बाद घर पहुंचने से लेकर अंतिम संस्कार तक की पूरी पुष्टि फोन पर ही अपने-अपने कार्यालयों से सभी जवाबदार अधिकारी लेते रहे। वही दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग एहतियात का हवाला देकर नोगांवा कालिया में जाकर थर्मल स्कैनिंग व परिवार के सदस्यों का सैंपल लेकर अपने कार्य के इतिश्री की। क्या कोरोना को लेकर यही है प्रशासनिक व्यवस्था और क्या ऐसी ही व्यवस्था के साथ प्रशासन कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने का दावा कर रही है ? यह अहम सवाल है। प्रदेश के आदिवासी जिलों के ग्रामीण अंचल तक दिन प्रतिदिन कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ-अलीराजपुर जिले की ही बात करें तो यहां कोरोना का मरीज मिलने के बाद, उक्त मरीज को एक से दो दिन मे स्वास्थ्य विभाग का अमला घर से ले जाकर आइसोलेट करती है। जब तक मरीज अपने परिवार के संपर्क में ही रहता है वही परिजन के साथ कंटेंनमेंट एरिया घोषित कर सभी सदस्यों की जानकारी स्वास्थ्य व पुलिस विभाग ले लेता है। क्वारंटाइन कर 5 से 7 दिन बाद सैंपल लिए जा रहे हैं, वही इस बीच कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अमला क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों में कोरोना को छोड़कर अन्य बीमारी से ग्रसित बुजुर्ग हो या घर का कोई सदस्य हो तो भी उनका उपचार नहीं किया जा रहा है, ये ही अभी की स्थिती में देखा जा रहा है। वही अपने आस-पास या गांव में कोरोना मरीज के आने के बाद जो व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से आगे आकर अपनी जानकारी देकर क्वारंटाइन होता है उनमें भी ऐसा भय पैदा किया जा रहा है कि, कोई व्यक्ति बाहर से भी दूरी बनाकर दरवाजे से बात करने की कोशिश करे तो उसे नहीं करने दी जाती है, जिससे अब ऐसे व्यक्ति भी कहने लगे कि क्वारंटाइन करने के बाद किसी प्रकार का स्वास्थ का हाल-चाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं लिया जाता है इतना ही नही कोई गरिब परिवार क्वारंटाइन में है उसको सरकार की ओर से दिया जाने वाला खाद्यान्न भी नही दिया जा रहा है। बात नोगावा कालिया की ही करे तो देख सकते है की प्रशासन ने अपनी जवाबदेही का किस तरह से निर्वहन किया हो सकता है प्रशासन सर्तक होता तो उस मुर्ख मॉ जो अपने पुत्र को इलाज के दौरान लेकर भाग गई और अपने ही पुत्र की हत्यारी बनी है, यदि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नही होती तो शायद आज वह बालक भी इस दुनिया में होता। इतना ही नही अगर जब डाक्टर ने कोरोना सिम्टम्स होने की बात कही तो फिर पुलिस से लेकर स्वास्थ्य विभाग इतना लापवाह क्यो रहा की वह संदिग्ध मरिज के घर तक जानकारी मिलने के बाद भी नही पहुचा और उसका अंतिम संस्कार के पुर्व शव परिक्षण तक नही करवाया प्रशासनिक इस लापरवाही के साथ क्या यह मान लिया जाए कि, स्वास्थ्य विभाग कोरोना के कोई सिम्टम्स नही होने पर या कोरोना सक्रंमित नही होने पर भी उसकी पॉजिटिव की पुष्टि की जा रही है। अगर ऐसा नही है तो फिर कोरोना के संदिग्ध होने की पुष्टि डाक्टर द्वारा ही करने के बाद भी प्रशासनिक अमला अपने कार्यलय में ही जमा रहा और दुसरे दिन एहतियात की बात कर जॉच करता रहा, ऐसी व्यवस्था को आखिर क्या समझा जाए ? क्या हम ऐसे ही प्रशासनिक व्यवस्था के साथ कोरोना से जल्द निजात पा लेंगे ? जवाब मिलेगा नहीं। इसलिए प्रशासन को चाहिए आम लोगों को जागरूक करने के साथ स्वयं भी टेलिफोनिक नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर अपनी जवाबदेही का निर्वहन करेगा तो ही कोरोना संक्रमण से निजात मिलने की परिकल्पना कर सकते हैं वरना नहीं।

न्यूज ब्रीफ

राहुल का सरकार से सवाल, 526 करोड़ का राफेल 1670 करोड़ रुपए का कैसे हुआ?

नई दिल्ली

राफेल विमान के भारतीय बेड़े में शामिल होने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना को बधाई दी है। हालांकि राहुल गांधी ने राफेल विमान को लेकर मोदी सरकार से कई सवाल पूछे हैं।. राहुल गांधी ने कहा कि, सरकार बताए कि 526 करोड़ का एयर क्राफ्ट 1670 करोड़ रुपये का कैसे हुआ? 126 की जगह 36 राफेल विमान क्यों खरीदे गए. एचएएल की जगह दिवालिया अनिल अंबानी को क्यों ठेका दिया गया?

हेटेरो लैब ने भारत में कोरोना की जेनेरिक दवा बाजार में उतारी

हैदराबाद

हैदराबाद स्थित हेटेरो लैब्स ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली फेविपिराविर जेनेरिक दवा पेश की है। इसे 'फेविविर' ब्रांड नाम के तहत बाजार में उतारा गया है। शहर स्थिति इस दवा कंपनी की जारी विज्ञप्ति में कहा गया है, हेटेरो को भारत के दवा महा नियंत्रक (डीसीजीआई) से फेविपिराविर के विनिर्माण और विपणन की मंजूरी मिल गई है। हेटेरो की कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 'कोविफोर (रेमडेसिविर)' के बाद फेविविर दूसरी दवा है जिसे कंपनी ने तैयार किया है। यह वायरल रोधी दवा है जसके चिकित्सकीय परिणाम सकारात्मक रहे हैं। यह दवा 29 जुलाई से देश की सभी खुदरा दवा दुकानों और अस्पतालों के दवा केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। दवा की बिक्री केवल डाक्टर की पर्ची के आधार पर होगी। इस दवा का उत्पादन कंपनी की विश्वस्तरीय फार्मूलेशन सुविधा वाली फैक्टरी में किया जा रहा है जिसे विभिन्न देशों के साथ ही अमेरिका की यूएसएफडीए और यूरोपीय संघ के संबंधित दवा प्राधिकरणों की अनुमति प्राप्त है।

5 अगस्त से खुलेगे जिम, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, नाइट कर्फ्यू भी हटा

नई दिल्ली।

केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक 3 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत पांच अगस्त से जिम और योगा इंस्टीट्यूट्स को खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं, रात के कर्फ्यू को भी हटा दिया गया है। हालांकि, कंटेनमेंट झोन में अभी भी लॉकडाउन लागू रहेगा। गृह मंत्रालय से जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार, देश में कॉलेज, स्कूलों और मेट्रो को अभी बंद रखा गया है। ये सभी अनलॉक 3 में नहीं खोले जा सकेंगे। इसके अलावा सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार और ऑडिटोरियम को भी बंद रखा गया है।

34 साल बाद आई शिक्षा की नई नीति, स्कूल-कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव

नई दिल्ली

मोदी सरकार ने शिक्षा की नई नीति बनाई गई है बुधवार को कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, उन्होंने बताया कि 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है, स्कूल-कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं,

श्री जावड़ेकर ने बताया कि, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है. 34 साल तक शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि, सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर 2 समितियां बनाई थीं. एक टीएसआर सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉ. के कस्तूरीरंगन समिति बनाई गई थी। नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर कर सकता है। उच्च शिक्षा में हम 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में 50 फीसदी तक पहुंचेंगे. इसके लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लाई जा रही है। सरकार की ओर से बताया गया कि, आज की व्यवस्था में 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर कोई छात्र आगे नहीं पढ़ सकता है तो उसके पास कोई उपाय नहीं है। छात्र आउट ऑफद सिस्टम हो जाता है. नए सिस्टम में ये रहेगा कि एक साल के बाद सर्टिफिक्रेट, दो साल के बाद डिप्लोमा, तीन या चार साल के बाद डिग्री मिल सकेगी।

भूमि पूजन के लिए 32 सेकंड का मुहूर्त

अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। भूमि पूजन होने के बाद राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। मंदिर का निर्माण पूरा होने में तीन से चार साल का वक्त लगेगा। मंदिर निर्माण के शुभारंभ कार्यक्रम को लेकर शासन-प्रशासन एकजुट होकर मुस्तैद है।

डेप्युटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। कोरोना संकट के कारण भूमि पूजन में शामिल न हो पाने वाले लाखों राम भक्तों को मंदिर निर्माण से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने कहा कि ट्रस्ट की भावना थी राम मंदिर भूमिपूजन कार्यक्रम में वे सारे लोग शामिल हों जिन्होंने राम मंदिर निर्माण आंदोलन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग किया था। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन का प्रसारण दूरदर्शन पर लाइव होगा। उन्होंने रामभक्तों से आग्रह किया कि शाम को अपने घर पर दीपक जलाकर दिव्य भव्य अवसर का स्वागत करें। ट्रस्ट की भी भावना सबको यहां के कार्यक्रम में शामिल करने की थी लेकिन वर्तमान कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थिति में ऐसा करना असंभव है। पीएम नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त के अयोध्या दौरे पर सुरक्षा का प्लान तैयार किया गया है।

अंबाला एयरबेस पर हुए पांचों राफेल लैंड, दिया गया वाटर सैल्यूट

नई दिल्ली

भारतीय वायुसेना की शक्ति में बढ़ोतरी हुई है,. फ्रांस से उड़ान भरने के बाद पांच राफेल लड़ाकू विमान भारतीय जमीन पर पहुंच गए हैं। हरियाणा के अंबाला एयरबेस में बुधवार को राफेल विमान लैंड हुए, जहां उनका स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। इस दौरान वायुसेना चीफ श्री भदौरिया भी मौजूद रहे. फ्रांस से मिलने वाली राफेल विमानों की ये पहली खेप है. इन विमानों ने मंगलवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये युएई में रुके और बुधवार दोपहर को अंबाला पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथसिंह की ओर से ट्वीट कर वायुसेना को बधाई दी गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि, राफेल का मिलना वायुसेना के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव होगा।

दुश्मन खबरदार

◂◂ राफेल फाइटर जेट्स मीटियर और स्काल्प जैसी मिसाइलों से भी लैस है। मीटियर विजुअल रेंज के पार भी अपना टारगेट हिट करने वाली अत्याधुनिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किमी है। स्काल्प करीब 300 किलोमीटर तक अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर सकती है। ◂◂ राफेल डीएच (टू-सीटर) और राफेल ईएच (सिंगल सीटर), दोनों ही ट्विन इंजन, डेल्टा-विंग, सेमी स्टील्थ कैपेबिलिटीज के साथ चौथी जनरेशन का फाइटर है। ये न सिर्फ फुर्तीला है, बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। ◂◂ राफेल सिंथेटिक अपरचर रडार (एक्र) भी है, जो आसानी से जाम नहीं हो सकता। इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है। किसी भी खतरे की आशंका की स्थिति में इसमें लगा रडार वॉर्निंग रिसीवर, लेजर वॉर्निंग और मिसाइल एप्रोच वॉर्निंग अलर्ट हो जाता है और रडार को जाम करने से बचाता है। ◂◂ राफेल का रडार सिस्टम 100 किमी के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है। राफेल में आधुनिक हथियार भी हैं, जैसे- इसमें 125 राउंड के साथ 30 एमएम की कैनन है। ये एक बार में साढ़े 9 हजार किलो का सामान ले जा सकता है। ◂◂ राफेल में लगी हैमर (हाइली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज) मीडियम रेंज मिसाइल है। ये आसमान से जमीन पर वार करती है। यह लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में भी मजबूत से मजबूत शेल्टर और बंकरों को तबाह कर सकती है।

बाबू का करिश्मा: आदिवासी विकास विभाग में बड़े बाबू अटकान ने पूरे परिवार के साथ जमाया अपना कब्जा

माही की गूंज, पेटलावद, राकेश गेहलोत

सरकारी कार्यालयों में बाबू शब्द सुनते ही सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने वाले समझ जाते हैं कि, बाबू सेट तो सब सेट। बड़े-बड़े अधिकारी बाबू की जेब मे रहते हैं और बाबू किसी भी कार्यालय की वो व्यवस्था है जिससे आप हर काम निकाल सकते है यह बात सामन्यतः सभी के सामने है पर कोई बाबू अपने बाबूगीरी प्रभाव के साथ ऐसा भी कर सकता है यह कभी आपने सपने में भी नही सोचा होगा।

स्वीपर से बड़े बाबू का सफर करने वाले ऐसे एक बड़े बाबू का खुलासा कर रहे है जिसने अपने प्रभाव व तगडी सेटिंग के साथ अपना पूरा कार्यकाल झाबुआ जिले में ही खपा दिया। पूरे मध्यप्रदेश में पेटलावद में आदिवासी विकास विभाग में अटकान एक ऐसा विरलय बाबू होगा जो अपने पूरे परिवार को आदिवासी विकास विभाग में न केवल कलेक्टर दर पर वरन् अंशकालिक दर से लेकर स्थाई कर्मी तक की नोकरी अपने परिवार को दिलवा कर सेट कर दिया, बल्कि पूरे सिस्टम को अपना ऐसा पंगु कर दिया कि, नोकरी के लिए न कोई विज्ञप्ति न कोई भर्ती के नियम बाबू पर लागू नही होकर अपने परिवार के सदस्यों को एक-एक कर अलग-अलग समय में विभाग का हिस्सा बना दिया। बाबू की कलम का जादू ऐसा रहा कि, हर

फर्जी नियुक्ति की लिखित शिकायत हुई जाँच भी हुई, नोकरी हटाने से लेकर वेतन रोकने और कार्य नही लिए जाने तक के अधिकारियों के आदेशों को बदलने पर मजबूर कर दिया।

पूरे मामले में एक प्राचार्य भी जुड़ा हुआ है जिसने अपने इस बाबू को तराने के लिए अपने पद का पूरा-पूरा उपयोग किया माही की गूंज आदिवासी विकास विभाग में पेटलावद विकास खण्ड में हुए इस भर्ती घोटाले और स्वीपर के पद से बड़े बाबू के पद पर पहुँचने और परिवार के सदस्यों को नोकरी पर लगाने की परत दर परत पूरा खुलासा मय दस्तावेजो के साथ किया जाएगा, जिसके बाद बड़े बाबू ओर बाबू पद की ताकत का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकेगा। रामचंद्र अटकान बाबू ने कैसे व किस तरह से अपने परिवार को विभाग के अधिकारियों को चांदी की जूती पहना-पहना कर अपना काम निकाल लिया और इस खुलासे के बाद वो बाबू भी सोचने पर मजबूर होगे जिनसे खुद के बच्चे ओर परिवार के निकट सदस्य आज भी पढें-लिखे होकर बेरोजगार घूम रहे हैं।

बाबू की सांठ-गांठ ऐसी की शिकायतों के बाद भी नही हुई कोई कार्रवाई

अटकान बाबू का खुलासा पढ़े गूंज के अगले अंक में...

डेढ़ साल में पार्टी में हो रही लगातार फूट कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही

कमलनाथ और दिग्विजय के राजनीतिक प्रबंधन में माहिर होने के बाद भी क्यों बिखर रही कांग्रेस?

भोपाल

मध्यप्रदेश में सिंधिया के इस्तीफे देने के बाद लगातार मप्र में कांग्रेस संगठन कमजोर होता जा रहा है यदि ऐसी ही स्थिति रही तो कांग्रेस को आगामी विधानसभा उपचुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के विधायक लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। इन इस्तीफों ने एक बार फिर से पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्यप्रदेश में कांग्रेस के अब तक 25 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। जबकि प्रदेश में दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी सत्ता में थी। महज डेढ़ सालों में पार्टी में हो रही लगातार फूट कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के होते हुए विधायकों का इस्तीफा सवाल खड़े करता है?

बताया जाता है कि कांग्रेस का मैनेजमेंट इस टूटन को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी और राजनितिक प्रबंधन में माहिर नेताओं का गणित भी फेल हो गया है। कांग्रेस नेताओं को विधायकों के पार्टी से जाने की भनक तक नहीं लग रही है। 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस 19 महीने में बिखर गई गई है। पांच महीने में उसके 25 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं।

खेमों में बंटी कांग्रेस

मध्यप्रदेश में कांग्रेस के बिखरने का मुख्य कारण खेमेबाजी है। कांग्रेस कई खेमों में बंटी हुई नजर आ रही है। वहीं, जानकारी का कहना है कि मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत को कांग्रेस भाप नहीं पाई। दिग्विजय सिंह पर राज्यसभा जाने के लिए सियासी ड्रामा रचने का आरोप लगाया गया।

कमलनाथ को सौंपी थी बागडोर

कमलनाथ छिंदवाड़ा से 8 बार लोकसभा का चुनाव जीते। केन्द्र सरकार में कई अहम विभागों के मंत्री रहे। कमलनाथ को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। 26 अप्रैल 2018 को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कमलनाथ के राजनीतिक अनुभव और मैनेजमेंट को देखते हुए मध्यप्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। जबकि पार्टी के युवा चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

चुनाव में दिखा प्रबंधन

मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के सबसे लोकप्रिय और बड़ा चेहरा थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जहां मैदानी स्तर पर मोर्चा संभाला वहीं, पूरे चुनाव के दौरान कमलनाथ का प्रबंधन नजर आया। कमलनाथ ने हर सीट पर उम्मीदवारों का सर्वे कराया और 15 सालों बाद राज्य में पार्टी को सत्ता दिलाई। हालांकि सत्ता में वापसी का कारण एक खेमा ज्योतिरादित्य सिंधिया को बता रहा था या तो दूसरा खेमा कमलनाथ को।

गुटबाजी के कारण बिखरी कांग्रेस?

विधानसभा चुनाव 2018 में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस का प्रबंधन लोकसभा चुनाव 2019 में ध्वस्त हो गया। मध्यप्रदेश में कांग्रेस को फैक्ट एक सीट मिली। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ विजयी रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह भी अपना चुनाव हार गए। सिंधिया की हार के बाद से कांग्रेस खेमों में बंटी नजर आई।

सिंधिया की बगावत

दिग्विजय सिंह सभाओं में कमलनाथ और अपनी दोस्ती की तारीफ करते रहे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की किसी को भनक तक नहीं लगी। सिंधिया समर्थक 18 विधायक कब भोपाल छोड़कर बैंगलुरू चले गए किसी को भी भनक नहीं लगी। कहा गया कि कमलनाथ-दिग्विजय की जोड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपेक्षा हो रही है। खुद कमलनाथ इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें और दिग्विजय सिंह को भरोसा नहीं था कि कांग्रेस के इतने विधायक सिंधिया के साथ चले जाएंगे।

नकुल नाथ के वीडियो से फिर माहौल गर्माया

भोपाल। मप्र के कांग्रेस विधायक आए दिन इस्तीफे देकर पार्टी को झटके दे रहे हैं, लेकिन वह आपसी कलह और गुटबाजी से उबर नहीं पा रही है। अब प्रदेश कांग्रेस में युवा नेतृत्व को लेकर गोलबंदी शुरू हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ के पुत्र व सांसद नकुल नाथ के 'मैं करूंगा नेतृत्व' वीडियो वायरल होने के बाद माहौल गर्मा गया है। खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र व पूर्व मंत्री जयवर्द्धन सिंह और नकुल नाथ के समर्थकों के बीच रार चल रही है। इस बीच भाजपा ने मौके का लाभ उठाते हुए कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर सांसद नकुल नाथ का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि आने वाले उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा। पिछले मंत्रिमंडल में हमारे जो युवा मंत्री थे, जैसे कि जीतू पटवारी, जयवर्द्धन सिंह, हरि बघेल, सचिन यादव, ओमकार मरकाम, ये सब अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मेरे साथ करेंगे। इस वीडियो के वायरल होते ही प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। वह वीडियो इस बात का संकेत भी है कि नेतृत्व को लेकर कांग्रेस में दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्रों की खींचतान खुलकर सामने आ गई है। उनके समर्थक इसका लाभ उठाते हुए गोलबंदी की धार पैनी करने में जुटे हैं।

पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने बजट पर उठाए सवाल

वित्तीय हालत पर श्वेत पत्र जारी करे सरकार

भोपाल

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारित विनियोग अध्यादेश के माध्यम से जो बजट लाया गया है उसमें विगत वर्ष की तुलना लगभग 28000 करोड़ की अनुमानित कमी की गई है। जिससे पता लगता है कि सरकार ने लेखानुदान के समय जो 40 परसेंट की वृद्धि दर बताई थी वह आंकड़ों की हेरा फेरी थी। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने आक्षेप व्यक्त किया है कि एफआरबीएम की ऋण लेने की सीमा बढ़ जाने के बावजूद भी बजट घट गया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र जो इस समय सामुदायिक चिंता का विषय है में बजट की कमी दर्शाती है कि सरकार हताश है और आगे का रास्ता उसे सूझ नहीं रहा है। भनोत ने कहा कि जीएसटी रिजीम में केंद्र सरकार ने वादा किया था कि 14% से कम वृद्धि होने पर वह राज्यों के घाटे की पूर्ति करेगी किंतु यह वादा पिछले साल भी नहीं निभाया गया और मध्य प्रदेश के लगभग 14000 करोड़ रुपए शेष रह गए थे।

केंद्र को मुनाफा

मध्य प्रदेश सरकार को और अन्य सरकारों को भी यह मांग करनी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई आयातीत कीमतों से केंद्र सरकार को जो भारी मुनाफा हुआ है कम से कम उसका 20% राज्यों को दिया जाए ताकि राज्य इस संकट काल में अपनी व्यवस्था को टिकाऊ बना सकें। तरुण भनोत ने सरकार को आगाह किया है कि लगभग 17 लाख प्रवासी मजदूर प्रदेश में आए है उनकी बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। सरकार की योजनाओं से उन्हें जीरा बराबर भी रोजगार नहीं मिला है शहरी मजदूर भी बेकाम हो रहा है कुशल मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध नहीं है। मजबूरी में इन मजदूरों का फिर से पलायन शुरू न हो जाए इसके लिए सरकार को बताना चाहिए कि बजट में उन्होंने क्या प्रावधान किए हैं।

मध्यम वर्ग के लिए कोई सोच नहीं

मध्यम वर्ग और सेवा क्षेत्र प्रदेश की जीडीपी में 40% से अधिक योगदान करता रहा है किंतु केंद्र और राज्य के बजट में उसकी पूरी तरह अनदेखी की गई है,क्या उसे राज्य की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहिये? लेकिन विधायक तोड़ सरकार के पास मध्यम वर्ग के लिए कोई सोच ही नहीं है। भनोत ने सरकार से वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का मांग की है । उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी बने और सदन से तथा प्रदेश की जनता से संपूर्ण बजट साझा करे। वर्तमान विनियोग अध्यादेश केवल एक बात की पुष्टि करता है कि मध्य प्रदेश में रामभरोसे सरकार जारी है।

उद्योग को बढ़ावा

अब एमपी बनेगा इन्वेस्टर डेस्टिनेशन

भोपाल

मध्यप्रदेश सरकार निवेशकों को लुभाने के लिए ईज ऑफ डूईंग बिजनेस में सुविधाएं बढ़ाकर उनके लिए रेड कारपेट बिछाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब प्रदेश में उद्योग, व्यवसाय करने वालों के लिए लगभग 55 तरह के काम ऑनलाइन किए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी उद्योग, निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग को सौंपी गई है। यह विभाग अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं बनवाने में मदद करेगा। बता दें, कि राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग ने तो उनके यहां उद्योगपतियों को दी जाने वाली सभी अनुमति या ऑनलाइन करने की पूरी तैयारी कर भी ली है। जबकि नगरीय प्रशासन विभाग, खनिज विभाग और खाद्य विभाग इसे अंतिम रूप देने में लगे हैं। यानी राज्य सरकार के किसी भी विभाग से अनुमति के लिए निवेशकों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सारे प्रमाणपत्र उन्हें ऑनलाइन मिल जाएंगे।

ऑनलाइन देख सकेंगे स्टेटस

उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश करने के लिए किस विभाग की अनुमति के लिए क्या दस्तावेज ऑनलाइन सबमिट करना है, यह विभाग भी वेबसाइट पर होगा। वह सारे दस्तावेज ऑनलाइन सबमिट करने के बाद विभाग उन्हें ऑनलाइन अनुमति देगा। जो भी प्रमाण पत्र जारी होना है वह भी ऑनलाइन ही जारी हो जाएंगे। इसके अलावा किसी भी विभाग से जुड़े जिस भी काम के लिए निवेशक ने आवेदन किया है उसकी प्रक्रिया किस स्थिति में है कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा वह भी उद्योगपति को ऑनलाइन दिखेगा।

सिंधिया आरोप सिद्ध करें या प्रदेश की जनता से मांगे माफी

भोपाल

ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पूर्व की कमलनाथ सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राजनीति गरमा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने इन आरोपों को सिद्ध करने की ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुली चुनौती दी है। दरअसल, मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अब इन्हीं आरोपों को लेकर कांग्रेस नेता सिंधिया पर हमलावर हो गए हैं।

भ्रष्टाचार का मांगा ब्यौरा

दिग्विजय ने ट्वीट कर लिखा है कि सिंधिया - पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, उन्हें खुली चुनौती है, नीचे विभागों का एक भ्रष्टाचार बताएं, वर्ना जनता से क्षमा मांगे। दिग्विजय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, परिवहन, श्रम, स्कूली शिक्षा राजस्व, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में हुए एक भ्रष्टाचार का ब्यौरा मांगा है। खास बात ये है कि दिग्विजय सिंह ने उन विभागों के भ्रष्टाचार की बात की है जो पिछली कमलनाथ सरकार में सिंधिया समर्थक मंत्रियों के पास थे। बता दे कि कमलनाथ सरकार में गोविंद सिंह के पास परिवहन, प्रभुराम चौधरी के पास शिक्षा, इमरती देवी के पास महिला-बाल विकास, प्रद्युम्न सिंह के पास खाद्य आपूर्ति जैसे विभाग थे।

नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस देश को बेचने का षड्यंत्र किया

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज कांग्रेस के स्पीक अप डेमोक्रेसी अभियान के तहत सोशल मीडिया के माध्यम से अपना वीडियो संदेश जारी कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। वर्मा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर देश को बेचने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। वर्मा ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हुए ऐसा घिनौना चित्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि गोवा की सरकार का मामला हो, कर्नाटक की सरकार तथा मध्य प्रदेश की जनमत के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र हो, वैसे ही राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार के विधायकों को धन बल के आधार पर खरीद फरोख्त करके सरकार को गिराने का घिनौना षड्यंत्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में किया जा रहा है। श्री वर्मा ने कहा कि यह एक ऐसा घिनौना चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें देश का आम नागरिक समझ ही नहीं पा रहा है कि वह क्या करें, क्या ना करें। जिन सरकारों को जनता चुनकर भेजती है उन्हीं सरकारों को सत्ता के लोभी लोग धनबल से तथा भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत से खरीद कर गिरा देते हैं।

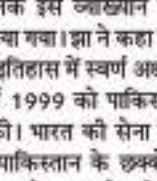

विस सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए भाजपा ने रणनीतिक तैयारी की

लोधी वोट बैंक को साधेगी साध्वी

भोपाल

मध्यप्रदेश में आगामी 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए भाजपा ने रणनीतिक तैयारी की है। इसमें भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती बड़ी भूमिका निभाएंगी। बता दें, कि इससे पहले पिछले कुछ वर्षों के उपचुनाव में उमा भारती को दूर ही रखा गया था। लेकिन आगामी समय में होने वाले उपचुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने जा रही है।

लोधी बाहुल्य चंबल में उमा की भूमिका

प्रदेश में आगामी जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चम्बल संभाग की हैं। इस क्षेत्र में लोधी वोटों की संख्या ज्यादा है। यहां साध्वी के समर्थकों की भी संख्या अच्छी खासी बताई जाती है। दूसरे लोधी समाज के ही प्रद्युम्न लोधी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वॉइन कर ली है। उनकी विधानसभा सीट बड़ा मलहरा भी उमा भारती के गृह क्षेत्र की है। प्रद्युम्न अब बड़ा मलहरा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। यही कारण है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की मप्र में होने वाले उपचुनावों में महती भूमिका रहेगी।

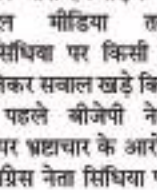

पीसी शर्मा ने सरकार को घेरा

बजट में गरीबों-छोटे दुकान दारों के लिए कुछ भी नहीं

भोपाल। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने विनियोग अध्यादेश के जरिए लाए बजट पर कहा , इतने दिनों में बजट आया वो भी 28 हजार करोड़ कम है, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग जैसे विभगों के बजट में कटौती की गई है। बजट में गरीबों और छोटे दुकानदारों के लिए कुछ भी नहीं है।

कोरोना पर सवाल- पीसी शर्मा ने कहा भोपाल में मरीज बढ़ गए हैं, भर्ती की सुविधा नहीं है इसलिए टेस्टिंग ही कम कर दी गई है सरकार ही असपताल में है। शिवराज सिंह के फोन में आरोग्य सेतु नहीं था, होता तो उन्हें जानकारी मिल जाती और वह संक्रमित नहीं होते, साथ ही सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि वरिष्ठ मंत्री और विधायकों को नजर अंदाज कर जिम्मेदारी बांटी गई है।

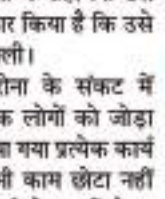

भोपाल। रविवार को खटलापुरा घाट पर स्थित मंदिर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समर्थक उनके शीघ्र स्वस्थ होने को लेकर यज्ञ करते हुए।

कोरोना खत्म करने सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने दिया मंत्र

हनुमान चालीसा का पांच बार पाठ करने से खत्म होगा कोरोना

पांच अगस्त को अनुष्ठान का रामलला की आरती के साथ घरों में दीप जलाकर समापन करें

मध्य प्रदेश की भोपाल लोकसभा सीट की भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोरोना वायरस महामारी से छुटकारे के लिए को अनूठा 'मंत्र' दिया. ठाकुर ने लोगों से आह्वान किया है कि देश से कोरोना वायरस की महामारी को समाप्त करने के लिए वे हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रज्ञा ने ट्वीट किया, आइए हम सब मिलकर कोरोना वायरस महामारी को समाप्त करने के लिए और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए एक आध्यात्मिक प्रयास करें।

उन्होंने लिखा, 25 जुलाई से 5 अगस्त तक प्रतिदिन शाम 7 बजे अपने घरों में हनुमान चालीसा का पांच बार पाठ कर प्रज्ञा ने कहा, पांच अगस्त को अनुष्ठान का रामलला की आरती के साथ घरों में दीप जलाकर समापन करें। ज्ञात हो कि पांच अगस्त को होने वाले राम मंदिर के शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।

स्वाध्याय मण्डल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने किया संबोधित

किताबों को रखने से कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं होता

भोपाल

अर्थपूर्ण जीवन वही है, जो जीवन और समाज का अध्ययन करता है। अध्ययन अनंत है। हमारा अंत हो सकता है लेकिन अध्ययन का अंत कभी नहीं हो सकता। अध्ययन केवल किताबी नहीं, बल्कि व्यवहारिक होना चाहिए। अध्ययन बिना जीवन अधूरा होता है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने रविवार को स्वाध्याय मण्डल में अध्ययन बिना जीवन अधूरा विषय पर व्याख्यान देते हुए कही। उनके इस व्याख्यान को फेसबुक पर लाइव किया गया। झा ने कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। 3 मई 1999 को पाकिस्तान में थोड़ी सी हरकत की। भारत की सेना ने 60 दिनों तक लगातार पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे और 21 वर्ष पहले आज के ही दिन 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को मात देकर भारत ने तिरंगा फहराया था। इसमें हमारे 527 जवान शहीद हुए और 1300 जवान घायल हुए थे। उन सभी शहीदों के चरणों में स्वाध्याय मंडल और अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। झा ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की चर्चा करते हुए हरियाणा की बेटी से बातचीत का जिक्र किया व कहा कि उस बेटी ने बेझिझक यह स्वीकार किया है कि उसे मां के व्यक्तित्व से प्रेरणा मिली।

उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट में स्वाध्याय मंडल द्वारा अनेक लोगों को जोड़ा गया है। संगठन के द्वारा दिया गया प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। जीवन में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, लेकिन समझना होगा कि जीवन क्या है, जीवन सुख दुख का मिश्रण है और आध्यात्मिक प्रसाद है।

समाज का होता है जीवन

उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने जीवन को अपना मानता है, लेकिन जीवन समाज का होता है। इस भाव से काम करने पर ईश्वर का अंश हममें जगा रहता है। उन्होंने कहा कि जीवन का पथ स्पष्ट होना चाहिए और ईश्वर का दिया जीवन समाज के काम आना चाहिए। झा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और पं. दीनदयाल जी का एकात्म दर्शन का आधार भी अध्ययन ही है। हमने अध्ययन में ही यह पाया कि संगठन की सफलता के लिए उसे कार्यकर्ता आधारित होना चाहिए। इसलिए हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित है, नेता आधारित नहीं है और इसीलिए संगठन का निरंतर विकास हुआ है।

पीएम बूथ स्तर के कार्यकर्ता को जोड़ने का प्रयास करते है

झा ने कहा कि अध्ययन के बिना कोई भी व्यक्ति संस्था, संगठन और अपने परिवार को प्रकाश नहीं दे सकता। अध्ययन समाज की रक्षा के लिए है। श्री झा ने कहा कि किताबों के रखने से कोई विद्वान नहीं होता, उनके अध्ययन से विद्वान होता है। जीवन का हर पल, हर क्षण अध्ययन ही है, जिससे व्यक्ति गौरवशाली दिशा की ओर जाता है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक सभी समाज को जोड़ने के लिए सतत अध्ययन करते हैं। श्री झा ने कहा कि बुझे दीये से दूसरे दीये नहीं जलते, उसके लिए जीवंत दीया ही चाहिए। इसलिए समग्र अध्ययन करें।

शिवराज सरकार की अधूरी मंशा से अब तक 450 पदों का पृष्ठाकंन नहीं हुआ

अधिकारी अतिथि विद्वानों की लिस्ट निकालने के लिए बना रहे हैं बहाने

माही की गूंज झाबुआ

मध्यप्रदेश के शासकीय कॉलेजों में वर्षों से शिक्षा देने वाले अतिथि विद्वानों को जब पिछली कमलनाथ सरकार ने नियमित भर्ती से नियुक्ति देकर सेवा से पृथक कर दिया था, तो वचन पत्र के बिंदु 17.22 के अनुसार नियमितीकरण और फॉलेन आउट को सेवा में लेने के लिए बड़े जोर - शोर से अतिथि विद्वानों का आंदोलन भोपाल के शाहजहांनी पार्क में दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक चलता रहा। इनके आंदोलन के प्रभाव से ही कमलनाथ सरकार ने 1367 पदो के स्थान पर 450 पदों की स्वीकृति फॉलेन आउट को पुनः सेवा में लेने के लिए कैबिनेट से दिसंबर माह में दी थी। जिसकी फाईल को पृष्ठाकंन के लिए वित्त विभाग को भेजा गया था।

परंतु मार्च में सत्ता पलट गई और सत्ता शिवराज सरकार के हाथो में आ गई। जिन्होंने कमलनाथ सरकार में अतिथि विद्वानों के भविष्य के लिए बड़ी-बड़ी डिंगे मारी थी। परंतु अब 129 के बाद भी शिवराज सरकार की मंशा से ही 450 पदों का पृष्ठाकंन आज तक नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से भी अतिथि विद्वान भेंट कर चुके है। लेंकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। जबकि इन 450 पदो पर मार्च में ही च्वाईस फिलिंग करवा ली गई थी। इन पदो के अलावा पहले से रिक्त 800 के लगभग पदो को मिलाकर लिस्ट निकलना थी। इस तरह शिवराज सरकार जानबूझकर अतिथि विद्वानों को गुमराह कर रही है। 8 माह तक पृष्ठांकन के नाम पर इनके परिवार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चाहते तो लिस्ट मार्च में ही निकल जाती, परंतु अफसरो की कूटनीति और सरकार की इच्छाशक्ति ने ऐसा नहीं होने दिया है।

इस संबंध में अतिथि विद्वान नियमितीकरण मोर्चा के मीडिया प्रभारी शंकरलाल खरवाडिया ने बताया कि, अफसरों से जब भी बात की जाती है, तो हमें हर बार एक ही जवाब मिलता है कि अभी फाईल पृष्ठांकन के लिए वित्त विभाग में गई है, जब आएगी तब सूची का प्रकाशन होगा। इस तरह अतिथि विद्वानों की अर्जी और निवेदन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिससे हम और हमारा परिवार कठिन जिंदगी गुजार रहे हैं। नियमितीकरण के नाम पर भी अभी दूर से ही लड्डू दिखा रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की सपनों की योजना को पलीता लगाती ग्राम पंचायत तारखेड़ी

फर्जी फोटो का जियो टेक कर कर दिया भुगतान , हितग्राही की भी मिलीभगत

माही की गूंज, पेटलावद

लाख देश के प्रधानमंत्री की ईमानदारी की कसीदे पड़े जाए लेकिन देश का सिस्टम इतना गया गुजरा ओर भ्रस्ट हो चला हैं कि किसी भी योजना के ग्राम पंचायत तक पहुँचते पहुँचते ये हालात हो जाती हैं भ्रस्ट देश के प्रधानमंत्री की सपनो की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना को भी नही छोड़ते , 2024 तक हर घर को पक्का बनाने की योजना को लेकर केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर 1,50,000 रुपए जिसमे 18,000मनरेगा की मजदूरी और स्वच्छ भारत योजना का शौचालय शामिल हैं और शहरी क्षेत्र में 2,50,000 रुपये देना तय किया लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर योजना को भारी पलीता लगया जा रहा है और ग्राम

जहा मकान बनना था वहाँ एक ईंट भी नही जोड़ी गई

पंचायतों द्वारा जिस प्रकार से योजना के नाम पर बंदरबाट की जा रही है उससे मोदी जी योजना 2024 में तो कही से कही पूरी होती नही दिख रही , विकास खण्ड पेटलावद की ग्राम पंचायत तारखेड़ी में ऐसा मामला सामने आया है जहाँ वर्ष 2018-19 में तारखेड़ी के देवीसिंह राजपूत के नाम से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुवा था लेकिन आवास के नाम पर एक ईंट भी नही जोड़ी गई और लगभग दो किस्तों का भुगतान कर दिया गया ,भुगतान भी हितग्राही के खाते में किया गया लेकिन भुगतान के लिए जियो टेक में दूसरे स्थान का फोटो देकर गलत तरीके से भुगतान करवाया गया साफहै इस बंदरबाट में ग्राम पंचायत के साथ साथ हितग्राही भी शामिल होगा जिसने बिना काम किये ही भुगतान ले लिया । ज्यादा जानकारी के लिए जब ग्राम पंचायत के सचिव हेमंत गरवाल से बात की तो कोई जानकारी नही दी गई और आकर मिलने की बात कहने लगा वही रोजगार सहायक से संपर्क किया तो उसने फोन तक नही उठाया , मुख्य कार्यपालन अधिकारी पेटलावद का मामले में कहना हैं कि हम दिखवाते कैसे ओर किसको भुगतान किया गया ।

घरेलू बिजली कनेक्शनों पर करोड़ों रुपए बकाया, बील नहीं भरने पर कट सकता है बिजली कनेक्शन

माही की गूंज झाबुआ

मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कपनी लि. झाबुआ के कार्यपालन यंत्री विकाससिंह मोरे द्वारा बताया गया कि, झाबुआ जिले के घरेलू विद्युत कनेक्शन के 86 हजार 5 सौ 15 उपभोक्ता है, जिन्होने 1 वर्ष से अधिक अवधि से विद्युत बिलों का भुगतान नही किए जाने से संभाग की घरेलू कनेक्शनों की बकाया राशि 26 करोड 67 लाख रूपए बकाया है। इसी प्रकार 8 सौ 68 व्यवसायिक उपभोक्ताओं पर राशि 1 करोड 18 लाख बकाया है। वही स्थानीय निकायों के 140 कनेक्शनों पर 15 लाख 96 हजार रूपए बकाया है, औद्योगिक क्षेत्र में 7 उपभौक्ताओं द्वारा 2.लाख 10 हजार की राशि बकाया है। श्री मोरे द्वारा यह भी बताया गया कि, उपभोक्ताओं से बार-बार सम्पर्क करने के बाद भी राशि का भुगतान नही किया जा रहा है। ऐसे सभी उपभौक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि, वितरण केन्द्र कार्यालय में जाकर विद्युत देयक का भुगतान करे अन्यथा कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेद कर वसुली हेतु कानूनी प्रकिया का उपयोग कर वसुली की जावेगी।

गांव की बेटी ने किया अपने माता पिता का नाम रोशन

माही की गूंज, जामली

गांव के बच्चो में भी कुछ करने के हौसले रहते हैं उसी तरह सोमवार को जब 12वी क्लास का रिजल्ट आया तो गांव में रहने वाली कोमल पिता लीलाधर पाटीदार 12वी कक्षा में 89.6 प्रतिक्षत अंक प्राप्त कर माता-पिता एवं विद्यालय का नाम रोशन किया है। कोमल पाटीदार शुरु से ही पड़ाई करने में अच्छे अंक प्राप्त करते आई है 10 वी की कक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। इस सफलता का श्रेय स्कूल ओर अपने माता-पिता को दिया है। कोमल जामली से रायपुरिया शासकीय विद्यालय पड़ने जाती हैं उसने बिना कोचिंग क्लास के घर पर ही पढ़ाई कर यह सफलता हासिल की है।

मुख्यमंत्री को झुठी शिकायत करने वाले को ले जाउंगी न्यायालय तक-सुश्री भूरिया

माही की गूंज च.शे. आजाद नगर

जोबट विधानसभा की विधायक सुश्री कलावती भूरिया पर अलीराजपुर व जोबट के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान तथा माधवसिंह डावर ने आरोप लगाया की संजय सिंह झारिया के साथ मिलकर कलावती ने तालाबों का फर्जी स्टीमेट बनाए गए जिसकी सूचना मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को दी है जिसमें शिकायत में दर्शाया की 5 तालाब फर्जी स्टीमेट के साथ तालाब बनाए गए है। दोनो पुर्व विधायक के द्वारा मुख्यमंत्री को की गई शिकायत पर जोबट विधायक सुश्री कलावती भूरिया ने कहा मेरे विरूद्ध झुठे आरोप के साथ मुख्यमंत्री को शिकायत की है मै झुठी शिकायत करने वाले को न्यायालय तक ले जाउगी।

अभियोजन अधिकारियों को वेबीनार के माध्यम से कोविड-19 प्रशिक्षण

माही की गूंज, थांदला

कोरोना से बचाव के साथ-साथ अभियोजन कार्य कैसे संपादित किया जाए इसे लेकर प्रदेशभर के अभियोजन अधिकारियों के लिए सोमवार को कार्यशाला आयोजित की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी वर्षा जैन के अनुसार प्रदेश भर के लगभग एक हजार अभियोजन अधिकारी वेबीनार के माध्यम से प्रशिक्षण में शामिल हुए। एमवाय. अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर पी. सी .ठाकुर ने कोरोना से बचाव और कोविड-19 प्रोटोकॉल और दिनचर्या में बदलाव के संबंध में उपाय बताएं। वेबीनार द्वारा प्रशिक्षण के दौरान अभियोजन अधिकारियों ने प्रश्न भी किये। करीब तीन घंटे चले वेबीनार प्रशिक्षण में लोक अभियोजन संचालक पुरुषोत्तम शर्मा ने भी अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। श्री शर्मा ने सभी को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण में बताए गए तरीके से अभियोजन कार्य संपादित करें। अभियोजन कार्यालय में जितनी आवश्यकता हो उतनी ही उपस्थिति रखी जाए । न्यायालय में उपस्थिति के संबंध में टेक्नोलॉजी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाए। कोविड-19 के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस एवं प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कार्य किया जाए ।कार्यालय में आने वाले आगंतुकों से भी सैनिटाइजर एवं मास्क के संबंध में विशेष ध्यान रखने को कहा जाए। श्री शर्मा ने कहां कि सभी अभियोजन अधिकारी अपने फिटनेस पर ध्यान दें। प्रतिदिन एक्सरसाइज विशेषकर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। उपरोक्त प्रशिक्षण में उपसंचालक अभियोजन के.एस. मुवेल, जिला लोक अभियोजक सौभाग्य सिंह खिंची, विशेष लोक अभियोजक रवि प्रकाश राय सहित समस्त लोक अभियोजन अधिकारीयों ने भाग लिया। बेबीनार आयोजित करवाने में प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी मध्य प्रदेश मौसमी तिवारी का विशेष योगदान रहा जिसके लिए समस्त अभियोजन अधिकारियों ने संचालक महोदय एवं श्रीमती तिवारी को धन्यवाद ज्ञापित किया।

ग्रामवासी कर रहे गस्त, फिर भी चोरों के हौसले बुलंद

माही की गूंज, परवलिया

ग्राम परवलिया में चोरिया थमने का नाम नहीं ले रही है। ग्राम में शांति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार ग्रामवासियों द्वारा अपने-अपने मोहल्ले में गस्त लगाना था, जिसके चलते सभी ग्रामवासी रात को 12 बजे से 4 बजे तक गस्त करते हैं, बावजूद फिर भी चोरिया रुक नहीं रही। रात में गांव के मेन चौराहे से खिमचंद अमलियार की बाइक चोरी हुई, साथ ही कुछ ही दूरी पर एक किराना व्यापारी की दुकान में सेंध मारकर चोरी करने की कोशिश की गई। लगातार बढ़ती चोरियों को देखते हुए ग्राम वासियों में भय का माहौल नजर आ रहा है। पास ही के ग्राम रुपगढ़ में कला पिता विरसिंग रावत के यहाँ से करीब 2 किलो चांदी के आभूषण की भी लूट हुई है। चोर खुले आम पुलिस को दे रहे चुनौती, लेकिन पुलिस कोई सुध नही ले रही है। शांति समिति की बैठक में हुई चर्चा के अनुसार स्कूल चौराहा एक संदिग्ध क्षेत्र बताया गया था जहाँ पॉइंट बनाने की बात को लेकर चर्चा की पर वहाँ कोई पॉइंट नही बना उसी की लापरवाही के चलते यह चोरी हुई है।

पप्पू के मुलाजिम पप्पू के नक्शे कदम पर चल, कर रहे कालाबाजारी

माही की गूंज खवासा

सुरेशचन्द्र उर्फ पप्पू पूरणमल जैन एक रूपए मे पात्र व्यक्तियों को मिलने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी कर गुजरात की मंडियों में खाद्यान्न बेच-बेचकर कराडो में खेलने वाले पप्पू के मुलाजिम भी उसी के नक्शे कदम पर चल सहकारी संस्थाओ में जाने वाले खाद्यान्न में प्रति ट्रक में सेंध लगाकर कालाबाजारी कर चॉदी काट रहे है। ऐसे कई मामले सामने आने के बाद भी पप्पू का मौन रहना ही कालाबाजारी को बडावा देना ही दर्शा रहा है।

बता दे कि, पप्पू पूरणमल का ट्रक पिछले दिनो मादलदा की सहकारी संस्था में खाद्यान्न खाली करने जा रहा था कि, ग्राम के बाहर एक झोपडी के आगे सडक पर गेहुँ से भरे कट्टे चालक एवं हम्मालो द्वारा उतार रहे थे कि, लोगो ने देख लिया ओर पीछा किया। शराबी ट्रक चालक व हम्माल गेहुँ से भरे कट्टो को सड़क पर ही छोड़ भाग निकले ओर खवासा में दुर्घटना ग्रस्त होते-होते ट्रक बचा। पप्पू के मेनेजर खवासा पहुँचे जिसके बाद मादलदा सहकारी संस्था में जाकर ट्रक में भरा खाद्यान्न खाली किया।

वही मंगलवार को भामल की आ.जा.सह. संस्था के अर्न्तगत क्षेत्र के तलावड़ा आ.जा.सह. उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न खाली करने पप्पू का ट्रक आया। ट्रक के कैबिन पर से चालक की जानकारी में होकर गेहुँ के तीन कट्टे ट्रक के साथ आए हम्मालो ने उतारकर उचित मूल्य की दुकान के समीप ही व्यापारी राजेन्द्र कुमार की दुकान पर जाकर उक्त तीन कट्टे गेहुँ के अपने निजी गेहुँ बताकर बेचने गए, तभी ग्राम के कुछ युवक व्यापारी की दुकान पर पहुँच गए ओर कहा, यह तो

सहकारी दुकान का गेहूं है जिस पर व्यापारी ने गेहूं खरीदने से मना कर दिया और गावं के युवको द्वारा तीन कट्टो को उठाकर उचित मूल्य की दुकान के आगे लेजाकर रखे व हम्मालों से पूछने लगे कि, यह गेहूं सरकारी दुकान का है तो इसे व्यापारी के यहां बेचने कैसे ले गए, तो हम्माल फिर भी उन गेहूं को अपने निजी गेहूं बताते रहे जिस पर युवकों व हम्मालों के बीच तू-तू, मैं-मैं होकर विवाद आपसी में बढ़ गया और दो हम्माल, यूवको से मारपीट कर धक्का देकर भाग चुके थे। मामला यहीं नहीं रुका उक्त जानकारी पुलिस व मीडिया को भी दी गई और उन तीन कट्टे गेहूं में से दो कट्टे युवकों ने पुनः उठाकर व्यापारी को ही पूर्ण रूप से दोषी ठहराने हेतु व्यापारी की दुकान के आगे परिसर में रख दिए, रात में पुलिस तलवाड़ा पहुंची, साथ ही पप्पू के मैनेजर भी पहुंचे और युवकों को गाड़ी पर नए हम्माल आए थे, उन्होंने गेहूं बेचने का प्रयास किया तो, इसमें हमारी क्या गलती है, कहने लगे। जिस पर मैनेजर व युवकों की बहस होने लगी। पुलिस ने युवकों को समझाकर वहां से हटाया और ट्रक खाली करवाकर रवाना किया। वही उक्त दो गेहूं के कट्टे जो युवकों ने ले जाकर व्यापारी की दुकान के आगे परिसर में रखे थे, वो दूसरे दिन तक भी वही बाहर पड़े रहे। खवासा चौकी प्रभारी रमेश कोली ने बताया कि, आज दो युवक चौकी में रिपोर्ट दर्ज करवाने आए है रिपोर्ट में युवकों ने बताया कि, व्यापारी के यहां हम्माल ने गेहूं के कट्टे ले जाकर रखें, जिसकी आपत्ति ली तो हम्मालों ने हमें मारा और भाग गए। युवकों का मेडिकल करवा के मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

संपादकीय

लोकतंत्र में संवैधानिक अग्नि परीक्षा का दौर

सर्वोच्च न्यायालय एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) के विशेषाधिकारों और दलबदल कानून की व्याख्या कर सकता है। हालांकि 1992 में शीर्ष अदालत के पांच न्यायाधीश फैसला दे चुके हैं कि किसी भी आशंका या भय के आधार पर स्पीकर की कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता। स्पीकर के निर्णय और किसी भी मामले में उनकी कार्रवाई के बाद ही अदालत न्यायिक समीक्षा कर सकती है, लेकिन वह भी सीमित होगी। स्पीकर एक व्यक्ति या प्रशासनिक पद नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक संस्था है। सदन में उनके फैसले 'सुप्रीम' होते हैं, लिहाजा उसमें दखल को लेकर न्यायपालिका को एक संयम रखना चाहिए। कमोबेश संविधान की लक्ष्मण-रेखा को तो लांघना ही नहीं चाहिए। ये स्थापनाएं अभी तक की हैं, जो सर्वोच्च अदालत के जरिए हमारे सामने स्थापित होती रही हैं, लेकिन इस बार कुछ और सवाल जुड़ गए हैं। सवाल भी सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों ने सुनवाई के दौरान उठाए थे। लिहाजा विधायक की सदस्यता की अयोग्यता, उसके आधार और कारण, असहमति की आवाज, विधायकों की बैठक में न आने का अर्थ अयोग्यता होगा क्या? पार्टी व्हिप और लोकतंत्र आदि पर नई व्याख्या की संभावनाएं बन रही हैं। कमोबेश दलबदल निरोधक कानून का कड़ा और स्पष्ट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि छोटे राज्यों की सरकारें गिरती और बनती रही हैं। विधायकों का 'आयाराम, गयाराम' जारी रहता है। जाहिर है कि पैसे का मोटा खेल भी होता रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत नहीं हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के सामने राजस्थान का विवाद है कि पार्टी में रहते हुए विधायकों को, सदन की कार्यवाही के बिना, स्पीकर अयोग्यता का नोटिस भेज सकते हैं या नहीं! सुनवाई आज शुरू होनी है। सवाल यह भी होगा कि ऐसी स्थिति में पार्टी व्हिप के मायने क्या हैं? चूंकि इस प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भी 'पक्ष' बनाया है, लिहाजा उसकी भूमिका पर भी कोई व्याख्या आ सकती है। जस्टिस गवई ने एक महत्त्वपूर्ण सवाल उठाया था कि स्पीकर कोर्ट में ही क्यों आए? व्याख्या यह भी स्पष्ट होनी चाहिए कि विधायक की अयोग्यता के आधार क्या हैं? क्या पार्टी विधायकों की सामान्य बैठक के संदर्भ में भी व्हिप लागू होगी? विधायक के आचरण से मूल्यांकन कैसे संभव है कि वह पार्टी लाइन के मुताबिक सक्रिय है अथवा पार्टी-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है? सर्वोच्च अदालत की न्यायिक पीठ किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी या सात न्यायाधीशों की नई संविधान पीठ को मामला सौंपा जाएगा? बहरहाल कोई नई व्याख्या आने से पहले 'राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री' के विरोधाभास और टकराव सामने आए हैं। विधायकों ने राजस्थान के 'राजभवन' में ही घंटों धरना दिया और विवादास्पद नारेबाजी की। विधायक किसकी 'तानाशाही' की बात कर रहे थे? मुख्यमंत्री ने किसके 'नंगे नाच' का उल्लेख किया? मुख्यमंत्री ने यहां तक बयान दे दिया कि यदि जनता 'राजभवन' का घेराव करती है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी! कानून-व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? बेशक संविधान के मुताबिक, राज्यपाल राज्य कैबिनेट की सलाह मानने और विधानसभा का सत्र बुलाने को बाध्य हैं, लेकिन संवैधानिक मर्यादा, गरिमा और अनुशासन भी तो बेहद महत्त्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री और विधायक राज्यपाल की छाती पर चढ़कर कोई निर्णय नहीं करा सकते। धमकियां भी लोकतंत्र की परिभाषा में नहीं आतीं। सुप्रीम अदालत नए सिरे से इन राजनीतिक प्रवत्तियों पर भी व्याख्या कर दे, तो वह देशहित में ही होगा। अतीत में भी राजभवनों में ऐसी राजनीतिक हरकतें होती रही हैं, यह कोई तार्किक आधार नहीं है। बहरहाल यह संवैधानिक अग्नि-परीक्षा का दौर है। यह वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण का भी आपदाकाल है, लिहाजा फैसला बेहद महत्त्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री भी संक्रमण से बचे हुए नहीं हैं, लिहाजा सावधानियां तो लेनी ही चाहिए। सबसे अहम तो यह है कि किसी ने राजस्थान सरकार से विश्वास मत प्राप्त करने की मांग ही नहीं की है। मुख्यमंत्री और सरकार बिलकुल स्थिर और सुरक्षित है। न्यायिक व्याख्या यह भी होनी चाहिए कि कितने अंतराल पर सत्र आहूत किया जा सकता है? आपात स्थितियों को अपवाद के तौर पर छोड़ा जा सकता है।

हम कैसे रामभक्त हैं?

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, यह एक बड़ी खुश-खबर है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को सभी पक्षों ने मान लिया है, यह भारत के सहिष्णु स्वभाव का परिचायक है लेकिन राम मंदिर बनानेवाला हमारा यह वर्तमान भारत क्या राम चरित का अनुशीलन करता है? हमारे नेताओं ने राम मंदिर बनाने पर जितना जबर्दस्त जन-जागरण किया, क्या उतना जोर उन्होंने राम की मर्यादा के पालन पर दिया? यहां मुझे कबीर का वह दोहा याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि %जो पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। राम के चरित्र को अपने आचरण में उतारना ही राम की सच्ची पूजा है। सीता पर एक धोबी ने उंगली उठा दी तो राम ने सीता को अग्नि-परीक्षा के लिए मजबूर कर दिया? क्यों कर दिया? क्योंकि राजा या रानी या राजकुमारों का चरित्र संदेह के परे होना चाहिए। सारे देश या सारी प्रजा या सारी जनता के लिए वे आदर्श होते हैं। यही सच्चा लोकतंत्र है। लेकिन हमारे नेताओं का क्या हाल है ? धोबी की उंगली नहीं, विरोधी पहलवानों के डंडों का भी उनपर कोई असर नहीं होता। देश के नेता तरह-तरह के सौदों में दलाली खाते हैं, उनपर आरोप लगते हैं, मुकदमे चलते हैं। और वे बरी हो जाते हैं। राम ने दशरथ की वचन-पूर्ति के लिए सिंहासन त्याग दिया और वन चले गए लेकिन आज के राम दशरथों को ताक पर बिठाकर सिंहासनों पर कब्जा करने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। वनवासी राम ने किस-किसको गले नहीं लगाया? उन्होंने जाति-बिरादरी, ऊंच-नीच, मनुष्य और पशु के भी भेदभावों को पीछे छोड़ दिया लेकिन राम नाम की माला जपनेवाले हमारे सभी नेता क्या करते हैं? राम ने लंका जीती लेकिन खुद उसके सिंहासन पर नहीं बैठे। न ही उन्होंने लक्ष्मण, भरत या शत्रुघ्न को उस पर बिठाया। उन्होंने लंका विभीषण को सौंप दी। लेकिन हमारे यहां तो परिवारवाद का बोलबाला है। पार्टियां-मां-बेटा पार्टी या भाई-भाई पार्टी या बाप-बेटा पार्टी या पति-पत्नी पार्टी बन गई हैं। राम ने राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलने की कोशिश की लेकिन हम रामभक्त हिंदुस्तानी लोकतंत्र को परिवारतंत्र में बदलने पर आमादा हैं! हम कैसे रामभक्त हैं?

(लेखक सुप्रसिद्ध पत्रकार और स्तंभकार हैं।)

राफेलः विश्व का बेहतरीन लड़ाकू विमान

योगेश कुमार गोयल, लेखक

लंबे इंतजार के बाद 29 जुलाई को भारतीय वायुसेना के बेड़े में पांच राफेल लड़ाकू जेट विमान शामिल हो जाएंगे। वैसे तो फ्रांसीसी कम्पनी 8 अक्तूबर 2019 को ही भारत को चार राफेल सौंप चुकी है और तभी से वहीं भारतीय पायलटों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा था, इसलिए पौने तीन माह पहले ये विमान भारत पहुंचने थे लेकिन कोरोना महामारी के कारण इनके भारत आने में विलम्ब हुआ। दो सीटों वाले प्रशिक्षण विमानों सहित आरबी सीरीज के पहले पांच राफेल जेट विमानों में फ्रांसीसी वायुसेना के टैंकर विमान से हवा में ही ईंधन भरा जाएगा और मिडल ईस्ट से आते समय भारत के अंबाला एयरबेस पर उतरने से पहले विमान में भारतीय आईएल-78 टैंकर द्वारा पुनः हवा में ही ईंधन भरा जाएगा। कुल 36 राफेल विमानों की दो स्क्वाड्रनों में से पहली '17 गोल्डन एरोज' भारत-पाक सीमा से करीब 220 किमी दूर अम्बाला तथा दूसरी पश्चिम बंगाल के हासीमारा केन्द्र में तैनाती होगी।

राफेल की विशेषताओं की बात करें तो इसे हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मिसाइल हमलों के लिए बहुआयामी भूमिका निभाने के लिए भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से परिष्कृत किया गया है। राफेल फ्रांस की विमान निर्माता कम्पनी 'दसॉल्ट एविएशन' द्वारा निर्मित दो इंजन वाला अत्याधुनिक मध्यम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) है, जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद माना जाता है। अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, माली तथा इराक में हुई जंग में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर चुके राफेल की टेक्नोलॉजी बेहतरीन है और इसमें कई ऐसी विशेषताएं हैं, जो इसे विश्व का बेहतरीन लड़ाकू विमान बनाने के लिए पर्याप्त हैं। यह हवाई हमला, वायु वर्चस्व, जमीनी समर्थन, भारी हमला, परमाणु प्रतिरोध इत्यादि कई प्रकार के कार्य बखूबी करने में सक्षम है। परमाणु बम गिराने की ताकत से लैस राफेल में इजरायल हेलमेट-माउंटेड डिस्प्ले, रडार चेतावनी रिसीवर, लो बैंड जैमर, दस घंटे की उड़ान डाटा रिकॉर्डिंग, इन्फ्रारेड खोज और ट्रैकिंग प्रणाली शामिल हैं। कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम राफेल विमान उल्का बीवीआर एयर-टू-एयर मिसाइल (बीवीआरएएम) की अगली पीढ़ी है, जिसे एयर-टू-एयर कॉम्बैट में क्रांति लाने के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा होने के कारण लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती।

फ्रांस में वर्ष 1970 में वहां की सेना द्वारा अपने पुराने पड़ चुके लड़ाकू विमानों को बदलने की मांग सरकार से की गई थी, जिसके बाद फ्रांस ने चार यूरोपीय देशों के साथ मिलकर एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान परियोजना पर काम शुरू किया। कुछ वर्षों बाद फ्रांस के साथ उन देशों के मतभेद हो गए और फ्रांस ने अपने बूते पर इस परियोजना

पर काम शुरू कर दिया। फ्रांस द्वारा निर्मित राफेल-ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को जबकि राफेल-सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को पहली उड़ान भरी थी। 'दसॉल्ट एविएशन' 1986 से लेकर 2018 के बीच कुल 165 राफेल विमान तैयार कर चुकी है। ये विमान ए, बी, सी तथा एम श्रेणियों में एक सीट, डबल सीट तथा डबल इंजन में उपलब्ध हैं। राफेल की लम्बाई 15.30 मीटर और ऊंचाई 5.30 मीटर है जबकि इसके विंग्स की लम्बाई 10.90 मीटर है। अमेरिका के लड़ाकू विमान एफ-16 की तुलना में यह मात्र 0.79 फुट ज्यादा लंबा और 0.82 फुट ऊंचा है। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ ही यह परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। अत्यंत घातक हथियारों से लैस ये विमान यूरोपीय मिसाइल निर्माता 'एमबीडीए' द्वारा निर्मित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मीटिअर मिसाइल के अलावा स्कैल्प क्रूज मिसाइल से भी लैस हैं। मीटिअर मिसाइल दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली अगली पीढ़ी की ऐसी मिसाइल है, जिसे हवाई लड़ाईयों में अत्यधिक कारगर माना जाता है।

रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक कोई लड़ाकू विमान कितना ताकतवर है, यह उसकी सेंसर क्षमता और हथियारों पर निर्भर करता है अर्थात् कोई लड़ाकू विमान कितनी दूरी से स्पष्ट देख सकता है और कितनी दूरी तक मार कर सकता है और राफेल इस मामले में बिल्कुल अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है। राफेल की विजिबिलिटी 360 डिग्री है, जिसके चलते यह ऊपर-नीचे, अगल-बगल अर्थात् हर तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। उन्नत तकनीक और परमाणु हमला करने में सक्षम राफेल का हर तरह के मिशन में उपयोग किया जा सकता है। यह हर तरह के मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी तुरंत भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। यह जमीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमानवाहक पोत से उड़ान भरने में भी सक्षम है और इसकी बड़ी खासियत यह है कि इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से थ्रीडी मैपिंग कर यह रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। राफेल में बैठे पायलट द्वारा दुश्मन की लोकेशन को देखकर बटन दबा देने के बाद बाकी काम इसमें लगे कम्प्यूटर करते हैं। कोई लड़ाकू विमान कितनी ऊंचाई तक जाता है, यह उसके इंजन की ताकत पर निर्भर करता है और केवल 1312 फुट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम राफेल 36 हजार फुट से लेकर 60 हजार फुट तक उड़ान भरने में सक्षम है, जो महज एक मिनट में ही 60 हजार फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। अधिकतम 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम राफेल 24500 किलोग्राम तक भार लेकर उड़ सकता है और इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक है।

मल्टीमोड रडार से लैस राफेल जेट विमान हवाई टोही, ग्राउंड सपोर्ट, इन-डेप्थ स्ट्राइक, एंटी-शर्प स्ट्राइक और परमाणु अभियानों को अंजाम देने में निपुण है। ऑप्ट्रॉनिक सिक्योर फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम से लैस राफेल में एमबीडीए एमआइसीए, एमबीडीए मीटिअर, एमबीडीए अपाचे जैसी कई तरह की खतरनाक मिसाइलें और गन लगी हैं, जो पल भर में दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। इसमें लगी मीटिअर मिसाइल सौ किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमान को भी पलभर में मार गिराने में सक्षम हैं। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी मिसाइल चीन-पाकिस्तान सहित एशिया में किसी देश के पास नहीं है। 150 किमी की बियोंड विजुअल रेंज मिसाइल, 300 किलोमीटर रेंज वाली हवा से जमीन पर मार वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस यह लड़ाकू विमान 4.5 जनरेशन के डबल इंजन से लैस है, जिसमें ईंधन क्षमता 17 हजार किलोग्राम है। इसमें लगी 1.30 एमएम की एक गन एक बार में 125 राउंड गोलियां चलाने में सक्षम है। केवल एक मिनट में विमान के दोनों तरफ से 30 एमएम की तोप से भी 2500 राउंड गोले दागे जा सकते हैं। यह ऊंचे इलाकों में लड़ने में भी माहिर है और इसमें एक या दो पायलट ही बैठ सकते हैं। एकबार में यह दो हजार समुद्री मील तक उड़ सकता है। परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवा से हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है और हवा से जमीन तक इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इसकी क्षमता पाकिस्तान के एफ-16 से ज्यादा है। पाकिस्तान और चीन की ओर से देश की सीमाओं की सुरक्षा को लगातार मिलती चुनौतियों के मद्देनजर राफेल विमान भारतीय वायुसेना को अभेद्य ताकत प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास इस समय जे-17, एफ-16 और मिराज जैसे जो उच्च तकनीक वाले लड़ाकू विमान हैं, वे तकनीक के मामले में राफेल से काफी पीछे हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

मप्रः पीढ़ीगत बदलाव को समझने की जरूरत

डॉ. अजय खेमरिया, लेखक

मध्य प्रदेश में बीजेपी के कुछ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के दलबदल के साथ ही मुरझाए हुए हैं। कैबिनेट गठन के बाद तो मामला सन्निपात-सा हो गया है। बड़े सुव्यवस्थित तरीके से पार्टी में एक विमर्श खड़ा किया जा रहा है कि बाहर से आये नेताओं को समायोजित करने से पार्टी का कैडर ठगा महसूस कर रहा है। कैडर के हिस्से की सत्ता दूसरे दलों से आये नेता ले जा रहे हैं। इस विमर्श के अक्स में बीजेपी की विकास यात्रा पर नजर दौड़ाई जाए तो स्पष्ट है कि सिंधिया के आगमन और उनकी धमाकेदार भागीदारी बीजेपी में कोई नया घटनाक्रम नहीं है। आज की अखिल भारतीय भाजपा असल में राजनीतिक रूप से गैर भाजपाईयों के योगदान का भी परिणाम है।

जिन सिंधिया को लेकर बीजेपी का एक वर्ग आज प्रलाप कर रहा है उन्हें याद होना चाहिये कि 1967 में सिंधिया की दादी राजमाता विजयराजे अगर कांग्रेस छोड़कर बारास्ता स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ में न आई होतीं तो क्या मप्र में इतनी जल्दी पार्टी का कैडर खड़ा हुआ होता? एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल विरोध के स्वर बुलन्द करने वालों से पूछा जा सकता है कि क्या वे जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके आसपास की विधानसभाओं में उनकी भीड़ भरी सभाएं सिंधिया की टक्कर में आयोजित की जा सकती है? क्या देश भर में सिंधिया की उपयोगिता से कोई इनकार कर सकता है? क्या मप्र में सिंधिया के भाजपाई हो जाने से कांग्रेस का अस्तित्व संकट में नहीं आ गया?

रही बात बीजेपी कैडर की तो वह सदैव यह चाहता ही है कि उसकी पार्टी के व्यास का विस्तार हो। यह निर्विवाद तथ्य है कि बीजेपी में उसकी रीति नीति को आत्मसात करने वाले ही आगे बढ़ पाते हैं। ऐसा भी नहीं कि बाहर से आये सभी नेताओं के अनुभव खराब हैं। मप्र में जनसंघ के अध्यक्ष रहे शिवप्रसाद चिनपुरिया मूल कैडर के नहीं थे। इसी तरह ब्रजलाल वर्मा भी बीजेपी में बाहर से आकर प्रदेश अध्यक्ष तक बने। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने मप्र में सिंधिया के दबाव में 14 मंत्री बना दिए हैं लेकिन पार्टी ने बहुत करीने से अपने नए कैडर को मप्र की राजनीति में मुख्यधारा में खड़ा कर दिया है। मसलन कमल पटेल, मोहन यादव, इंदर सिंह परमार, अरविंद भदौरिया-को मंत्री बनाकर खांटी संघ कैडर को आगे बढ़ने का अवसर दिया गया है। उषा ठाकुर, भूपेंद्र सिंह, भारत सिह कुशवाहा, प्रेम पटेल, कावरे मीना सिंह जैसे जन्मजात भाजपाईयों को जिस तरह मंत्री बनाया गया है उसे आप पार्टी का सोशल इंजीनियरिंग बेस्ड पीढ़ीगत बदलाव भी कह सकते हैं।

जाहिर है जो मीडिया विमर्श बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया के आगे सरेंडर दिखाता है उसके उलट मप्र में नए नेतृत्व की स्थापना को भी देखने की जरूरत है। मप्र में पार्टी के मुखिया के रूप में बीडी शर्मा की ताजपोशी क्या किसी ने कल्पना की थी।बीडी शर्मा असल में मप्र की भविष्य की राजनीति का चेहरा भी हैं, वे पीढ़ीगत बदलाव के प्रतीक भी हैं। यानी मप्र में दलबदल के बावजूद वैचारिक अधिष्ठान से निकला कैडर मुख्यधारा में सदैव बना रहा है।

मप्र राजमाता सिंधिया को बीजेपी ने सदैव राजमाता बनाकर रखा, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बारी है कि वे अगर अपनी दादी के सियासी अक्स को अपने जीवन में 25 फीसदी भी उतार सकें तो वह भी महाराजा की तरह प्रतिष्ठित पायेंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने तो उनको राजमाता की तरह ही अवसर उपलब्ध करा दिया है। वैसे बीजेपी में बाहर से आये नेताओं को उनकी निष्ठा के अनुसार सदैव प्रतिष्ठा मिली है। मप्र की सियासत के ताकतवर चेहरे डॉ. नरोत्तम मिश्रा का परिवार कभी कांग्रेस में हुआ करता था उनके ताऊ महेश दत्त मिश्र कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे है लेकिन नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी ने इस पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद आगे बढ़ाया।

सवाल यह है कि जब बीजेपी का राजनीतिक दर्शन पार्टी को सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बनाने का है तब मप्र में सिंधिया प्रहसन पर सवाल क्यों उठाये जा रहे हैं? क्या यह तथ्य नहीं है कि सिंधिया के कारण ही मप्र जैसे बड़े राज्य में पार्टी को फिर से सत्ता हासिल हुई। क्या सवाल उठाने वाले चेहरों ने सत्ता बनी रहे, इसके लिए अपने खुद के योगदान का मूल्यांकन ईमानदारी से किया है? क्या इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि सिंधिया प्रहसन पर आपत्ति केवल उन लोगों को है जो जीवन भर बीजेपी में रहकर दल से बड़ा देश अपने मन मस्तिष्क में उतार ही नहीं पाए।

तथ्य यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से मप्र में कांग्रेस नेतृत्व विहीन होकर रह गई है।आज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह 70 पार वाले नेता हैं और दोनों के पुत्रों को मप्र की सियासत में स्थापित होने में लंबा वक्त लगेगा। सिंधिया का आकर्षक व्यक्तित्व और ऊर्जा, बीजेपी के लिए मप्र में अपनी जमीन को फौलादी बनाने में सहायक हो सकती है। सिंधिया के लिए भी बीजेपी एक ऐसा मंच और अवसर है जिसके साथ सामंजस्य बनाकर वह जीवन की हर सियासी महत्वाकांक्षा को साकार कर सकते हैं क्योंकि यहां एक व्यवस्थित संगठन है, अनुशासन है और एक सशक्त आनुषंगिक नेटवर्क है।

आवश्यकता इस बात की है कि बीजेपी संगठन की प्रभावोत्पादकता सत्ता साकेत में कमजोर न हो। संगठन और विचार का महत्व बनाए रखने की जवाबदेही मूल पिंड से उपजे नेताओं की ही होती है। बीजेपी के वैचारिक अधिष्ठान में प्रचारक की तरह आचरण अपेक्षित है। जो नेता इस अधिष्ठान को समझते हैं उनका उत्कर्ष यहां बगैर वकालत के निरन्तर होता रहा है। इसलिए सिंधिया हों या पायलट, सामयिक रूप से जो सियासी उत्कर्ष में सहायक हो उन्हें लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिये। अगर ऐसे नेताओं के अंदर समन्वय और वैचारिक अबलंबन का माद्दा होगा तो वह मूल विचार के लिए उपयोगी ही होंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

पुलिस तंत्र में रिफॉर्म की जरूरत

डॉ. रमेश ठाकुर

पुलिसिया सिस्टम बूढ़ा हो चुका है। उसे उर्जावान बनाने की जरूरत है। इसको लेकर फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय पर दबाव बनना शुरू भी हो गया है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में यह मुद्दा उठा है। बीते एकाध महीनों में कई राज्यों की पुलिस की जो हरकतें सामने आई है उसको देखते हुए पुलिस महकमे में बदलाव की जरूरत महसूस होने लगी है। पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह काफी समय से इसकी मांग कर रहे हैं। पुलिस का रवैया निश्चित रूप से सरकारों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें, कितना भी अच्छा काम करें, पर जब सुरक्षा तंत्र क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम हो जाता है तो उसकी जबावदेही हुकूमतों पर आ जाती है। तब लोग पुलिस या सुरक्षा सिस्टम को नहीं कोसते, सीधे सरकारों को कठघरे में खड़ा करते हैं। दरअसल, चुनावी के वक्त सुरक्षा की गारंटी जन प्रतिनिधि ही देते हैं। जाहिर है सवाल उन्हीं से होंगे। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा के अलावा ज्यादातर राज्यों की पुलिस के काम करने के तौर-तरीकों पर मौजूदा वक्त में सवाल खड़े हो रहे हैं। हाल की कुछ घटनाओं ने रोंगटे खड़े किए हैं। पुलिस का आपराधिक प्रवृत्तियों को संरक्षण देना, फरियादियों की शिकायतों को अनदेखा करना, उनकी शिकायतों पर एक्शन लेने की जगह आरोपियों तक उनकी सूचनाएं पहुंचाना आदि हरकतों का हाल में पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली से सटे मेरठ में लव जिहाद का मामला इस वक्त चर्चा में है। घटना को लेकर कई हिंदू संगठन आक्रोशित हैं। संगठन के लोग सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। दिल्ली में कुछ जगहों पर हिन्दु सेना द्वारा जिहादियों के पुतले भी फूंके गए हैं। अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिखित में जवाब मांगा है कि आखिरकार हिंदुस्तान में लव जिहाद के नाम पर कबतक हिन्दू महिलाओं की बलि चढ़ती रहेगी? मुद्दा वास्तव में बड़ा चिंतनीय है। मेरठ लव-जिहाद मसले को पुलिस अगर समय रहते हैंडल कर लेती तो शायद माँ-बेटी की जान बच सकती थी। पुलिस को पता था एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू बनकर मां-बेटी को अपने चुंगल में फंसा चुका है। बावजूद इसके पुलिस ने जिहादी पर कोई करवाई नहीं की, नतीजा दोनों मां-बेटी जिहादी के हाथों मारी गईं। दरअसल, यह वक्त की जरूरत है कि पुलिस के पूरे सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए। ऐसे मामलों में पुलिस के लचीलेपन और उसकी घोर लापरवाही पर कई सवाल खड़े होते हैं। मेरठ में एक लव जिहादी ने बड़ी बेरहमी से मां-बेटी को मौत के घाट उतारा। देखा जाय तो इस कृत्य में पुलिस भी बराबर की भागीदार है। करीब डेढ़ महीने बाद मां-बेटी प्रिया व कशिश के कंकाल मोहम्मद शमशाद नामक जिहादी के घर से बरामद हुए। शमशाद ने अमित गुर्जर बनकर प्रिया को अपने प्रेमजाल में फँसाया था और शादी की थी। शादी के कुछ ही दिनों में जब जिहादी का भांडा फूटा तो प्रिया ने थाने में जाकर कोतवाल से शिकायत की। कोतवाल ने उसकी सूचना शमशाद को दे दी। शमशाद ने कोतवाल को चढ़ावा देकर मामले को शांत कर दिया। पुलिस ने प्रिया की शिकायत को कचरे के डिब्बे में डालकर मामले को रफा-दफा कर दिया। जिहादी शमशाद कई तरह के अनैतिक कार्यों में संलिप्त था, दिखावे के लिए बुक बाइंडिंग का काम करता था। ये बात भी पुलिस को पता थी। शमशाद जब घर मोटी रकम लेकर आता था, तो प्रिया उनसे पैसों के संबंध में पूछती थी। इसको लेकर आपस में झगड़ा होता था। उसके पहले इस्लाम मानने को लेकर भी प्रिया का शमशाद से झगड़ा हुआ था। प्रिया को सबकुछ पता चल गया था, वह विरोध करने लगी थी और अपनी सहेली चंचल को सभी बातों से अवगत कराती थी। प्रिया जब शमशाद का खुलकर विरोध करने लगी तो उसने वही किया जो अंत में एक जिहादी करता है। शमशाद ने अपने साले के साथ मिलकर मां-बेटी को ठिकाने लगाने का षड्यंत्र रचा। रात में सोते समय दोनों को मार डाला और शवों को कमरे में दबा दिया।

प्रिया की सहेली चंचल उसे लगातार फोन करती, कोई रिप्लाई नहीं आता। उसे अनहोनी का शक हुआ। तभी चंचल ने पुलिस के पास जाने का निर्णय लिया। वह एसएसपी के पास पहुंची। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और एक जांच टीम गठित की। पूरे मामले की छानबीन का ज़िम्मा एक तेजतर्रार इंस्पेक्टर को सौंपा। जिन्होंने दो दिनों के भीतर ही पूरे मामले को एक्सपोज कर डाला। मां-बेटी का कंकाल शमशाद के घर से बरामद कर लिया गया। मामला जैसे ही बाहर आया चारों ओर हाहाकार मचा है। चंचल इससे पहले पुलिस में दो दफे और शिकायत कर चुकी थी जिसपर कोई करवाई नहीं की गई। पुलिस ने अगर करवाई की होती तो निश्चित रूप से दोनों मां-बेटी की जान बचाई जा सकती थी।

सवाल ये है कि सिस्टम कब संवेदनशील होगा? कब पुलिस में सुधार होगा? भाजपा विधायक राजेश कुमार मिश्रा भरतौल की मांग तब और जायज लगने लगती है, जिसमें उन्होंने सरकारों द्वारा गुंडों की बनाई लिस्ट की भांति भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों की भी सूची तैयार करने की मांग की। क्योंकि खाकी में भी अनगिनत भेड़िए छिपे हैं, जो फरियादियों की समस्याओं को सुलझाने के बजाय माफियाओं की आवभगत करते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश का बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग दबाव बना रहा है कि पुलिस के पूरे सिस्टम को आधुनिक किया जाए। जिस तरह से उन्होंने इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि विभागों में कार्यरत नाकारा और भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया, ठीक उसी अंदाज़ में पुलिस विभाग में नजरें घुमाने की आवश्यकता है। राज्यों में सुधार तभी होगा, जब केंद्र सरकार से कोई मुकम्मल पहल शुरू होगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

राजस्थान में अपने ही चक्रव्यूह में फंसी भाजपा

सिद्धार्थ शंकर, लेखक

राजस्थान का सियासी ड्रामा पिछले 20 दिन से चल रहा है। इस सियासी ड्रामे में कई मोड सामने आए। कांग्रेस और भाजपा अपने ही बिछाए हुए जाल में खुद फंसकर फड़फड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ सरकार को गिराने का गेम प्लान तैयार किया गया था। वह सफल भी रहा। उसी तर्ज पर भाजपा ने राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराने का प्रयत्न किया। इसमें वह सफल अभी तक नहीं हो पाए हैं।राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर सतर्क थे।

राज्यसभा के चुनाव को प्रभावित करने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त का जो प्रयास किया गया था।उसको निष्फल करने के लिए उन्होंने फोन टेप कराकर, और जब सचिन पायलट ने बगावत की तो सरकार गिराने के षड्यंत्र का अपराधिक प्रकरण दर्ज कराकर भाजपा की शह पर मात्र देने का काम किया।अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने के लिए किसी भी हद पर जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ मामला दर्ज कराकर, दो भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर केंद्र सरकार की प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया। इसके बाद से यह मामला बिगड़ता चला गया। अपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाने और 102 विधायकों को एकजुट करके एक जगह पर एकत्रित करके अशोक गहलोत ने भाजपा के सरकार गिराने की कोशिश पर कड़ा जवाब दिया। इसके जवाब में राजस्थान प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री स्वीकार करने की गुगली फेंककर गहलोत समर्थक विधायकों पर दल बदल के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी पायलट को पार्टी के अंदर बात करने और पार्टी में वापस आने का दबाव बनाकर विद्रोह को दबाने का संकेत देकर भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ा दी थी। सचिन पायलट ने भी यह कह दिया कि वह है भाजपा में शामिल नहीं होंगे। जिसके कारण अशोक गहलोत खुद के जो विधायक दल बदल करने के लिए तैयार थे वह भी शांत होकर बैठ गए। सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अशोक गहलोत की सरकार गिराकर वह स्वयं मुख्यमंत्री बनने का दबाव भाजपा के ऊपर बना रहे थे। इसका दबाव जब भाजपा पर पड़ा, तब भाजपा भी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गई। भाजपा अध्यक्ष पूनिया के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नाराज हो गई। जिसके कारण भाजपा में भी 2 फाड़ हो गए।एक पक्ष सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता हस्तांतरण के लिए तैयार था। वहीं वसुंधरा राजे इसके खिलाफ हो गई। जिसके कारण राजस्थान के विधायक, विशेष रूप से सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट के विधायक सशंकित हो गए। मामला हाईकोर्ट में चला गया। विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को लेकर कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई थी। वह न्यायिक समीक्षा के दौरान टाय टाय फिस्स हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट गया, यहां से भी अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष को कोई राहत नहीं मिली। उल्टे मामला संवैधानिक समीक्षा में उलझ जाने के कारण, विधानसभा अध्यक्ष को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी।

राजभवन से कोई राहत अभी तक अशोक गहलोत को नहीं मिली है। उन्होंने अपने सारे पांसे फेंके,विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर दूसरी बार भी मंत्रिमंडल की अनुशंसा कर दी। राज्यपाल ने 21 दिन का नोटिस देने और शर्तों के साथ सत्र बुलाने की अनुमति देकर अशोक गहलोत के लिए मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस हो जाने के बाद राज्यपाल ने 21 दिन का नोटिस देने की बात कहकर मामला होल्ड कर दिया है। जिसके कारण अशोक गहलोत को अपने विधायकों को अपने खेमे में रोक पाना मुश्किल हो रहा है। राजस्थान में खुलकर सौदेबाजी हो रही है।जिसके कारण अब अशोक गहलोत को अपनी सरकार बचा पाना मुश्किल होता जा रहा है। अशोक गहलोत अभी तक बड़ी आक्रमक मुद्रा में पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। राज्यपाल के निर्णय के बाद वह अपने आक्रमक रुख को कायम रख पाएंगे, यह कहना मुश्किल है। उन्होंने अभी तक अपनी सरकार बचाने की लड़ाई खुलकर लड़ी है। वह समर्पण की मुद्रा में नहीं है। उनके भाई के ओर उनके समर्थकों के यहां छापे के बाद भी उन्होंने समर्पण करने के स्थान पर केंद्रीय गृहमंत्री और सचिन पायलट के साथ गए विधायकों पर निशाना साध कर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भी इस विवाद में शामिल कर लिया है। ऐसी स्थिति में अब यह मामला एक-दो दिन में नहीं सुलझा, तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावनाएं बन गई हैं।

राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति, राजनीतिक अस्थिरता, कोरोना संक्रमण इत्यादि को देखते हुए केंद्र सरकार कभी भी राजस्थान विधानसभा को स्थगित कर, 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि भाजपा के लिए अनुकूल राजनीतिक समीकरण नहीं बनने पर, विधानसभा भंग कर बिहार के साथ राजस्थान के चुनाव भी कराए जा सकते हैं।सारे देश में पिछले 20 दिनों से राजस्थान में गहलोत सरकार को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह से शह और मात का खेल खेला जा रहा है। इसमें न्यायपालिका भी कहीं ना कहीं विवादों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा अध्यक्ष के जिस नोटिस पर इतना विवाद मचा हुआ है। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच पहले ही निर्णय कर चुकी है। जिस तरह से राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नया मोड़ दिया है।सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसले ने दरकिनार करते हुए नई व्यवस्था दी है। इसको लेकर भी देशभर में न्यायालयीन कार्रवाई को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है।राजस्थान में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि राजस्थान की सत्ता भाजपा और कांग्रेस के गले में फ़ांस की तरह गड गई है। जो दोनों को ही तकलीफ दे रही है। इसको निकालने का रास्ता दोनों के लिए आसान नहीं रहा। सर्जरी के रूप में सत्ता संतुलन केंद्र सरकार के पक्ष में है। जिसके कारण लगता है कि अब राष्ट्रपति शासन ही राजस्थान में एकमात्र विकल्प है। अशोक गहलोत को जहां अपनी सरकार बचाने की चिंता है, वहीं केंद्र सरकार को भी अपने मंत्री और पार्टी के मनोबल को बनाए रखने की चिंता बनी हुई है। इसके लिए दोनों किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं।

ओशो

जिसे गिराना हो, पहले उसे ऊपर चढ़ाना होगा

जिसे गिराना हो, पहले उसे चढाना होगा। नहीं तो गिराइएगा कैसे? पहले सहारा देना होगा कि ऊंचे शिखर पर पहुंच जाये, तभी गिराया जा सकता है खाइयों में। तो लाओत्से कहता है कि अगर गिरना न हो तो चढने से सावधान रहना। लोग तो चढायेंगे, लेकिन वे गिराना चाहेंगे। वे तो तुम्हें सहारा देंगे कि बढो। और जब वे चढा रहे हैं। तब तुम यह देख भी न पाओगे कि वे गिराने का इंतजाम कर रहे हैं.. और जब वे तुम्हें हाथ का सहारा दे रहे हैं। तब तुम बडे प्रसन्न हो रहे हो, लेकिन तुम्हें दूसरे पहलू का कुछ भी पता नहीं है। जो तुम्हें मान देते हैं। वे ही तुम्हारा अपमान करेंगे, जो तुम्हें आदर देते हैं। वे ही तुम्हारे अनादर का कारण हो जायेंगे। क्योंकि आदर का दूसरा हिस्सा अनादर है। जैसे जन्म मृत्यु में बदलेगा ही, वैसे ही आदर भी अनादर में बदलेगा।

इमर्सन ने एक बहुत अनूठी बात खिली है। इमर्सन ने अपने जीवन भर के अनुभव के बाद लिखा है। लिखा है- एवरी ग्रेट मैन फाइनली टर्न्स टु बी ए बोर, सभी बडे लोग अंततः बोर सिद्ध होते हैं।, उबाने वाले सिद्ध होते हैं..

इधर पिछले तीस-चालीस वर्षों के इतिहास से हम समझ सकते हैं। कि क्या इसका अर्थ। आपको ख्याल है कि पिछले तीस-चालीस वर्षों में जितने बडे लोग पैदा हुए जमीन पर, एक दिन लोगों ने उन्हीं को सम्मानित किया, शिखर पर उठाया, और उनके ही जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें उतार कर नीचे डाल दिया। चर्चिल की कैसी प्रतिष्ठा थी दूसरे महायुद्ध में ! लेकिन युद्ध के बाद चर्चिल सत्ता में वापस नहीं आ सका। और जिन्होंने उसे पूजा था और सोचा था कि इंग्लैंड के इतिहास में इससे बडा महापुरुष नहीं हुआ, वे ही उसे सत्ता में लाने से रुकावट डालने को तैयार हो गये। दि गॉल को उतरना पडा सत्ता से युद्ध के बाद। स्टैलिन ने रूस को बचाया और बनाया। शायद ही किसी एक आदमी ने किसी राष्ट्र को इस भांति बनाया। उसने जो पाप भी किये वे भी उसी राष्ट्र को बनाने के लिए किये। उस एक आदमी के हाथ की मेहनत ही पूरा सोवियत रूस है। लेकिन युद्ध के बाद रूस ने स्टैलिन को अपदस्थ कर दिया। और मरने के बाद, आपको पता है, क्रेमलिन के बाहर के चौराहे से उसकी लाश भी वापस हटा दी गई। लेनिन के पास ही उसकी लाश रखी गई थी, वह भी मरने के बाद हटा दी गई। उसको क्रेमलिन के चौराहे पर नहीं रहने दिया। क्या कारण होगा? च्यांग काई शेक को चीन ने इतना आदर दिया था जिसका हिसाब नहीं। च्यांग काई शेक अब ह्रजदा है, लेकिन चीन में कोई पूछने वाला नहीं। चीन की जमीन पर च्यांग काई शेक पैर भी नहीं रख सकता है। चीन की जनता उसको नंबर एक दुश्मन मानती है। रूजवेल्ट ने अमेरिका को बचाया, दूसरे महायुद्ध में विजय के निकट लाया। सारी दुनिया को युद्ध से बचाने में रूजवेल्ट का गहनतम हाथ था। लेकिन युद्ध के बाद अमेरिकी संसद ने एक संशोधन किया अपने विधान में और उस संशोधन के द्वारा रूजवेल्ट वापस प्रेसीडेंट न हो जाये, इसकी व्यवस्था कर ली।

क्या होगा इस सबके पीछे राज? व्यक्तियों का सवाल नहीं है। लाओत्से जिस जीवन के द्वंद्व की बात कर रहा है, और जिस लय की, उसका सवाल है। आदर के पीछे छिपा है अनादर, सम्मान के पीछे छिपा है अपमान।

भाजपा को रास नहीं आ रही भागवत कथा...!

ओमप्रकाश मेहता, लेखक

एक जमाना था जब पूव जनसंघ, विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल आदि सभी संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सहायक संगठन माने जाते थे, अर्थात् संघ प्रमुख इन सभी का 'सुपर बॉस' होता था, किंतु आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है, पूर्व जनसंघ जो अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में विद्यमान है, उस पर राजनीति और सत्ता का इतना गहरा रंग चढ़ गया है कि वह संघ व उसके प्रमुख को अपने अधीन मानने लगी है और संघ प्रमुख के विचारों पर टीका-टिप्पणी करने लगी है, यही हाल विहिप और बजरंग दल का हो गया है और ये भी संघ व उसके प्रमुख को सत्ता का रूतबा दिखाने लगे है।

भारत में करीब एक सौ साल से तो कांग्रेस व संघ ही विद्यमान रहा है, कांग्रेस का जन्म जहां 1889 में हुआ था तो संघ का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में हुआ और पूर्व जनसंघ का जन्म तो काफी बाद में हुआ। किंतु यह सही है कि जनसंघ का जनक संघ ही माना गया, जिसे संघ ने अपना राजनीतिक संगठन घोषित कर रखा था, बीसवीं सदी के मध्य में भारत की आजादी के आसपास ही जनसंघ का जन्म हुआ जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गया, अर्थात् आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी उम्र महज चालीस साल ही है जबकि संघ उसके दादाजी की उम्र अर्थात् करीब सौ वर्षीय है, अब ऐसे में यदि आज के पोते को आज की हवा लग गई और उसे दादाजी का गलत काम पर गुर्राना अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए समय दोषी है, भाजपा नहीं, हाँ..... यह अवश्य है कि भाजपा अपनी पुरानी सामाजिक संस्कृति भूल गई और मौजूदा हालातों में ढल गई, फिर जब से भाजपा पर सत्ता का रंग चढ़ा है, तब से तो उसकी स्थिति एक बहुप्रचलित कहावत- ङ्कपहले तो मियाँ बावले, ऊपर से पीली भाँगङ्घ के अनुरूप हो गई, जब सत्ता किसी को भी अपने समकक्ष नहीं समझती तो फिर संघ या संघ प्रमुख क्या चीज है? .....और यह सब तभी होता है, जब भाजपा सत्ता में रहती है, खासकर वर्तमान में? क्योंकि जब अटल जी - आडवानी जी का राज था, तब संघ की स्थिति ऐसी नहीं थी। .....अब तो आप जबसे डॉ. मोहनराव भागवत संघ प्रमुख बने है, तभी से अब तक का इतिहास उठाकर देख लो उनके हर कथन को विवादास्पद बना दिया गया सत्तारूढ़ भाजपा के महापुरूषों द्वारा फिर वह बिहार चुनावों के पहले के उनके वक्तव्य हो या आज दलबदलुओं के बारे में भागवत जी द्वारा भोपाल में की गई टिप्पणी हो? भागवत जी जहाँ भाजपा की पुरातन संस्कृति और मौजूदा सत्ताप्रधान कार्यप्रणाली के बीच तालमेल नहीं बैठा पा रहे है और दलबदलुओं को भाजपा संगठन के समर्पित सदस्य नहीं मानते वहीं सत्ता का रंगीन चश्मा चढ़ाये भाजपा के दिग्गज दलबदलुओं को अपने वर्षों पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं से अधिक तवज्जोह दे रहे है, यहीं भाजपा की सोच भागवत जी को रास नहीं आ पा रही है, वे भाजपा को अपने जमाने के उसी जनसंघ के चश्में से देख रहे है, जिसमें पार्टी के सिद्धांतों व परम्पराओं को प्राथमिकता दी जाती रही थी। भागवत जी परिवार के बुजुर्ग की हैसीयत में सब कुछ पूर्वानुसार देखना चाहते है, जो कि मौजूदा हालातों में संभव नहीं है अर्थात भागवत जी अपने संघ का वर्चस्व कायम रखकर अपनी बात 'आदेश' के रूप में मनवाना चाहते है और आज की भाजपा को नई पीढ़ी पारिवारिक बुजुर्ग की तरह दादाजी को एक कमरे में कैद करके रखना चाहती है, मुख्यरूप में आज संघ और भाजपा का यही विवादित स्वरूप है। चूंकि संघ प्रमुख व भाजपा दोनों के चश्में और उनसे देखने का नजरिया मेल नही खा रहा है, इसीलिए संघ व उसके प्रमुख अपने आपकों उपेक्षित समझ रहे है, संघा प्रमुख भाजपा को पुराने जनसंघ के सांचे में ढला देखना चाहते है जो अपने सिद्धांतों व मर्यादाओं से बंधी हो और .....भाजपा चूंकि सत्ता मद्य सेवन कर उसके नश में झूम रही है, इसलिए उसे अपने बुजुर्ग संगठन व उसके प्रमुख के आदर-सम्मान का कोई भान नही है। वैसे यदि भाजपा को संगठन व उसके समर्पित सिद्धांतों की कसौटी पर कसकर मौजूदा दलबदलुओं के माहौल में देखा जाए तो सत्ता अहम् नजर आती है और संगठन के सिद्धांत गौण, यही आज का परिदृष्य है, अब इसे किसी भी नजरिये से देख लीजिए, यह आप पर है.....।

शॉर्टकट की संस्कृति और हमारी पुलिस

विभूति नारायण राय, पूर्व आईपीएस अधिकारी

थानों को मिलाकर जिले के आंकड़े बनते हैं, लिहाजा कहा जा सकता है कि जिले में लूट के बीस फीसदी मामले बढ़े हैं। इन आंकड़ों की समीक्षा रेंज, जोन, पुलिस मुख्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय तक होती है और इन्हीं के आधार पर विभिन्न स्तरों के अधिकारियों का मूल्यांकन होता है।

नक्शा जरायम तीन साला मुकाबिलेवार नामक यह छड़ी हर थाने और जिले से उच्चाधिकारियों को भेजा जाने वाला कागज का एक टुकड़ा है, जिस पर पिछले तीन वर्ष के अपराधों का तुलनात्मक विवरण दर्ज होता है। मैंने सालों-साल बड़ी दिलचस्पी से इस दस्तावेज का अध्ययन किया है। इधर उर्दू खत्म करने के चक्कर में सुना है कि इसका नाम बदल दिया गया है। बकौल शेक्सपीयर नाम में क्या रखा है, इसलिए काम इस कागज का पुराना ही है। थाना और जिला, पुलिस की बुनियादी इकाइयां हैं और इनके प्रभारियों की कार्य-क्षमता का मूल्यांकन इसी के आधार पर होता है। मसलन, किसी थाने में अगर पिछले साल दस लूट की घटनाएं दर्ज थीं और यदि इस वर्ष बारह हो गईं, तो नतीजा निकलेगा कि लूट के अपराध बीस फीसदी बढ़ गए।

यह जानना रोचक होगा कि जादू की इस छड़ी से अपराध कम कैसे किया जाता है? जब आबादी बढ़ रही हो, बेतरतीब शहरीकरण हो रहा हो, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बढ़ रही हो, एक संस्था के रूप में परिवार अनुशासित कर सकने की क्षमता खो रहा हो, गरज यह कि अपराध बढ़ाने के सारे कारण मौजूद हों और पूरी दुनिया में अपराध बढ़ रहे हों, तब ऐसा क्यों होता है कि हमारे देश में अपराध कम होते रहते हैं? उत्तर जादू की छड़ी के पास है। जैसे ही अपराध के तुलनात्मक आंकड़े ऊपर तक पहुंचते हैं, अच्छे-बुरे संदेश आने लगते हैं। यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि राज्य अपराध कम करने के लिए कटिबद्ध है। मगर राज्य के पास न तो इतना धैर्य व संसाधन हैं, और न ही उसकी दिलचस्पी इसमें है कि वह पुलिस व न्याय प्रणाली में ऐसे सुधार करे, जिनसे अपराध नियंत्रित हो सकें, इसलिए वह शॉर्टकट तलाशता है। और यह शॉर्टकट है एफआईआर दर्ज न करना। पिछले साल किसी भी श्रेणी में जितने मुकदमे लिखे गए, इस साल उनसे कम लिखना।

मेरा अनुमान है कि उत्तर भारत में दो-तिहाई से अधिक मुकदमे आसानी से दर्ज नहीं होते। पैसा, रसूख या पैरवी के बल पर कुछ दर्ज भी हो जाएं, तब भी आधे से अधिक दर्ज हुए बिना रह जाते हैं। इसके लिए आप सिर्फ थाना-इंचार्ज को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैंने ऊपर एक सूची दी है, जिन तक तीन साल के अपराधों के विवरण जाते हैं और इन सबको पता होता है कि वे झूठ का पुलिंदा देख रहे हैं और सब खुश होते रहते हैं कि उनके 'अथक प्रयासों' से अपराध नियंत्रण में हैं। सरकार लंबे-लंबे विज्ञापनों के जरिए दावे कर सकती है कि उसके शासन में सब कुछ ठीक है। उत्तर प्रदेश में 1960 के दशक में जब एनएस सक्सेना पुलिस के मुखिया थे, पुलिस थानों में ईमानदारी से मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए, तो अपराध कई गुना बढ़ गए, पर तब उन्हें मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह का समर्थन हासिल था। जैसे-जैसे मुख्यमंत्री के विरोधियों ने अपराधों की बाढ़ का हल्ला मचाया, वैसे-वैसे यह समर्थन कमजोर पड़ता गया और फिर सब कुछ यथावत होता गया।

मुकदमे दर्ज न करने से वास्तविक अपराध कम नहीं होता और जब जनता त्राहिमाम करने लगती है, तो सरकारें पुलिस को त्वरित न्याय करने के आदेश दे देती हैं। फिर पुलिस अपराधियों को पकड़कर अदालत में पेश करने की जगह 'मुठभेड़' में मार डालती है या नए चलन के अनुसार, कम से कम उनके पैर में तो गोली मार ही देती है। अपराध से लड़ने के लिए गठित एक संस्था को खुद अपराधी बनाने का इससे बदतर और क्या तरीका हो सकता है? अपराधियों को मारकर अपराध काबू में आ सकता, तो वह सब न घटता, जो पिछले एक महीने में हमें देखने को मिला। नृशंस हत्यारों विकास दुबे और उसके साथियों को निपटाने में जिन दिनों कानपुर पुलिस लगी थी, उन्हीं दिनों उसी शहर में एक अपहरण हुआ और परंपरा के मुताबिक थाने में उसका मुकदमा नहीं लिखा गया। अपहृत के घर वाले तब तक दर-दर भटकते रहे, जब तक कि उन्हें उसकी हत्या की सूचना नहीं मिल गई। इन्हीं दिनों गाजियाबाद के एक पत्रकार की हत्या समेत दर्जनों ऐसी वारदातें हुईं, जो टल सकती थीं, अगर शुरू में ही एफआईआर दर्ज हो गई होती। पुलिस से फर्जी एनकाउंटर कराने का परिणाम कितना कारुणिक हो सकता है, इसका अंदाज हम हाल में भरतपुर के पूर्व विधायक राजा मानसिंह की हत्या के अपराध में सुनाए गए दंड से लगा सकते हैं। यह माना नहीं जा सकता कि इतने प्रभावशाली व्यक्ति का 'एनकाउंटर' छोटे स्तर के पुलिसकर्मियों ने अपनी मर्जी से किया होगा, पर सजा उन्हीं को हुई। विकास दुबे के 'एनकाउंटर' में भी कहीं ऐसा ही न हो। जरूरत है कि सरकार विकास दुबे मामले में अदालती निजाम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को गंभीरता से ले। इसके साथ ही पुलिस को कानून का सम्मान करने वाली एक सभ्य संस्था बनाने की आवश्यकता है। पर इन सबके लिए बड़े धैर्य और संसाधनों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो हर अपराध पर एफआईआर दर्ज करने की आवश्यकता है। एनकाउंटर के नाम पर हत्याएं बंद करनी पड़ेंगी। पर क्या सरकारें शॉर्टकट की संस्कृति से मुक्त होना चाहेंगी?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सफलता उन्हीं विद्यार्थियों की प्रतिक्षा करती है जो लगन और निष्ठा से अध्ययन करते हैं

माही की गूंज सनावद

माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल द्वारा आयोजित वर्ष 2020 की हायर सेकण्डरी परीक्षा में स्थानीय एमडी जैन हायर सेकण्डरी स्कूल के छात्र जयवर्धनसिंह, राजेन्द्रसिंह परिहार ने कक्षा 12वीं वाणिज्य संकाय में 61.6 प्रतिशत नावेद मुनव्वर खान ने विज्ञान संकाय (गणित) में 73.4 प्रतिशत तथा कमल गंगाराम ने कृषि विज्ञान संकाय में 75.6 प्रतिशत् अंक प्राप्त किए। छात्र जयवर्धनसिंह परिहार ने प्रसन्नसा व्यक्त करते हुए बताया कि, वे बी.कॉम. की शिक्षा ग्रहण कर चारटेड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं।

कार्यालय प्रभारी महेन्द्रसिंह पंवार ने बताया कि, हाईस्कूल परीक्षा में संस्था के छात्र हर्ष संजय गुप्ता निमारखेड़ी ने 92.75 प्रतिशत् अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवांवित किया। संस्था के प्राचार्य डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन, प्रबंधक हेमेन्द्र कुमार जैन तथा स्टॉफ सदस्यों ने छात्र को बधाई देते हुये भविष्य में उच्च सफलता प्राप्त करने की मंगलकामना की। डॉ. नरेन्द्र कुमार जैन तथा महेन्द्रसिंह पंवार ने बताया कि जो विद्यार्थी अनुशासित रहकर संस्था में नियमित रहते हैं तथा निष्ठा एवं लगन से अध्ययन करते हैं तो सफलता ऐसे विद्यार्थियों की प्रतिक्षा करती है।

आवास योजना का नही मिल रहा पैसा, सीएम हेल्पलाईन में शिकायत के सौ दिन बाद भी नही हुआ निराकरण

माही की गूंज सनावद

नगर में आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही की राशि नही मिलने पर नगर की कुछ वार्ड के रहवासियों ने सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत की थी। सीएम हेल्पलाइन की समयावधि 100 दिन से अधिक पूर्ण होने के बाद भी इस मामले में कोई निराकरण नहीं होने के बाद सीएमओ एमआर निगवाल ने शिकायतकर्ताओं को बुलाकर उनसे चर्चा की। इस मौके पर शिकायतकर्ताओं ने भी सीएमओ से चर्चा कर शिकायत वापस लेने की बात कही।

नगर में आवास योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में हितग्राहियों को आवास योजना का पैसा दिया जाना है। लेकिन शासन द्वारा नगर पालिका के खाते में आवास योजना से संबंधित कोई भी राशि नही भेजी गई। जिस कारण आप लोगों के खातों में पैसा नहीं पहुंच पाया। आवास योजना की राशि आप के खातों में ही आएगी। आप लोगों ने जो शिकायत की है, उसका कोई मतलब नहीं। ऐसी शिकायत आप आगे भी करेंगे, तो भी कुछ नहीं होगा। शासन से राशि आने के बाद ही हितग्राहियों को पैसा दिया जाएगा। यह बात सीएमओ निगवाल ने सीएम हेल्पलाइन पर आवास योजना के मामले में अलग-अलग शिकायतकर्ता से चर्चा कर रहे थे। शिकायतकर्ताओं को सीएमओ निगवाल ने बताया कि, शासन द्वारा ही ऊपर से पैसा नहीं डाला गया। साथ ही जिन लोगों के नाम आवास योजना में स्वीकृत हो गए हैं। उन लोगों की राशि सीधे उनके खाते में जाएगी। इस दौरान शिकायतकर्ता मोहन प्रजापति, रितेश कटारिया, राजेश प्रजापत, विकास प्रजापत, मोहम्मद हफीज, अनिल बाबूलाल, भोलेनाथ भटानीय, नीलोफर बी, रामगीर गोस्वामी सहित अन्य शिकायतकर्ता से चर्चा की। शिकायतकर्ताओं ने भी सीएमओ की बात पर संतोष जाहिर करते हुए अपनी-अपनी शिकायत वापस लेने का भरोसा दिलाया। निगवाल ने बताया कि, इन सभी की शिकायत को 100 दिन से अधिक हो जाने के बाद इसमें निराकरण करना है। इसके बाद सभी शिकायतकर्ताओं को बुलाकर वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। जिसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत वापस लेने की बात कही।

धरने पर बेठे तुलावटियों को एसडीएम ने दिया आश्वासन

माही की गूंज सनावद

कृषि उपज मंडी में पिछले 8 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे तुलावटियों से मंगलवार को एसडीएम मिलिंद ढोके ने चर्चा की। साथ ही उनकी समस्याओं को सुनने के साथ ही शासन स्तर पर इसके प्रयास हो रहे हैं, ऐसी जानकारी दी। श्री ढोके ने तुलावटियों से चर्चा करते हुए कहा कि, यह शासन के आदेश है जो भी निर्णय होंगा ऊपरी स्तर पर होंगा। इसलिए आप लोग कोरोना संक्रमण में धरने को छोड़ प्रशासनिक स्तर पर बात करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर इसका समाधान करने के जल्द प्रयास किये जायेंगे। एसडीएम ढोके के साथ नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल एवं तुलावट्टी मौजूद थे।

रेल्वे के सीआरएम श्री शर्मा ने किया रेलवे ट्रैक का निरीक्षण

माही की गूंज सनावद

रेलवे के सीआरएम आरके शर्मा ने सोमवार को मथेला से निमाड़खेड़ी तक 44 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की ओएचई सेफ्टी का निरीक्षण किया। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 40 मिनट में निमाड़खेड़ी से मथेला तक 44 किमी की दूरी स्पेशल ट्रेन से तय की। शाम 7:10 बजे निमाड़ खेड़ी से शर्मा ने निरक्षण शुरू किया। शाम 7:50 बजे मथेला पहुंचे। इस दौरान ट्रेन की स्पीड कहीं भी कम नहीं हुई। जबकि पहली बार 44 किलोमीटर के ट्रैक पर इलेक्ट्रॉनिक इंजन से निरीक्षण हुआ। इससे पहले सुबह 11:30 बजे शर्मा ने खंडवा स्टेशन पर अधिकारियों से चर्चा कर रेलवे ट्रैक ओर ओएचई के संबंध में जानकारी ली। श्री शर्मा सुबह 11:30 बजे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन से निकले, निरीक्षण करते हुए शाम 4 बजे निमारखेड़ी पहुंचे। सेल्दा से निमाड़खेड़ी के बीच 35 किमी तक सेल्दा पावर प्लांट का ट्रैक हैं, इस पर इलेक्ट्रॉनिक लाइन का काम नहीं हुआ है। श्री शर्मा ने कहा ट्रैक और ओएचई लाइन दोनों का काम ठीक है, इस रूट पर डीजल इंजन के बजाय कोयले का इलेक्ट्रॉनिक इंजन ले जाने की शुरुआत करें।

हालांकि शर्मा के इस निर्देश के बावजूद भी मथेला से सेल्दा पावर प्लांट तक इलेक्ट्रॉनिक इंजन नहीं जा सका। क्योंकि निमाड़खेड़ी से सेल्दा के बीच 35 किमी निजी ट्रेक पर ओएचई का काम नहीं हुआ। श्री शर्मा ने निमाड़खेड़ी से सनावद इंदौर महू रेलवे ट्रेक के सबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान रेलवे के विभिन विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

विधायक ने हाट बाजार के दिन को लॉकडाउन से मूक्त करने की कलेक्टर से की मांग

माही की गूंज सनावद

विधायक सचिन बिरला ने क्षेत्र में लगातार दो दिन के लॉकडाउन को अव्यवहारिक और गैर जरूरी बताते हुए सोमवार को लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार को लॉकडाउन से मुक्त करने की मांग जिला प्रशासन से की है।

श्री बिरला ने खरगोन जिला कलेक्टर को लिखे एक पत्र में यह मांग की है। पत्र में लिखा है कि, सनावद में प्रति सोमवार और बड़वाह में प्रति मंगलवार को साप्ताहिक हाट बाजार लगाया जाता है। हाट बाजार के दिन आसपास के ग्रामों के श्रमिक, कृषक और आम नागरिक आवश्यक खाद्य एवं अन्य दैनिक उपयोगी अत्यावश्यक सामग्री का क्रय करते हैं। इसके अलावा हाट बाजार के दिन फेरीवाले और छोटे व्यापारी अपनी दुकानें हाट में लगाते हैं और इससे उनका जीवन यापन होता है। पिछले चार माह से कोरोना लॉकडाउन के कारण समाज का प्रत्येक वर्ग किसान, मजदूर, व्यापारी और आमजन आर्थिक तंगी से त्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में हाट बाजार वाले दिन सोमवार को भी लॉकडाउन करना सभी के लिए कष्टदायक है। इसलिए क्षेत्र में हाट बाजार के दिन सोमवार को लॉकडाउन से मुक्त रखा जाए। वैसे भी क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण नियंत्रित है और नागरिक सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए आमजन की आवश्यकताओं को देखते हुए व्यापक जनहित में सोमवार हाट बाजार को लॉकडाउन से मुक्त रखा जाए। श्री बिरला ने सप्ताह में केवल एक दिन रविवार को ही लॉकडाउन रखने की मांग की है।

श्री बिरला ने बताया कि, क्षेत्र के नागरिकों की भी पुरजोर मांग है कि, साप्ताहिक हाट बाजार सोमवार के दिन को लॉकडाउन से मुक्त रखा जाए।

शराबी थानेदार ने गैस ऐजेन्सी के प्रबंधक की थाने में की पिटाई, थानेदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

माही की गूंज सनावद

शनिवार की रात को घर लौट रहे रुद्राक्ष गैस एजेंसी के प्रबंधक और युवा कांग्रेस के महासचिव पंकज मालाकार की पुलिस थाने में निर्मम पिटाई के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने कड़ी निंदा की। और मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफएफआईआर और निलंबन की कार्यवाही करने की मांग की है।

इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, नितिन रावत और पवन इंगला आफ्ताब हिलाल ने थाना प्रभारी ललितसिंह डांगुर से मुलाकात कर समूचे घटनाक्रम से अवगत कराया और विरोध प्रकट किया। पीड़ित मालाकार ने बताया कि शनिवार की रात्रि नशे में धुत्त एसआई दीपक तलवारे और उसके वाहन चालक ने पुलिस थाने में कपड़े उतरवा कर अमानवीय तरीके से अकारण मारपीट की और अत्यंत अपमानजनक व्यवहार किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि, मालाकार नगर के एक प्रतिष्ठित नागरिक और जनप्रतिनिधि हैं और एसआई तलवारे और उसके वाहन चालक ने एक प्रतिष्ठित नागरिक के साथ अकारण अपराधियों जैसा व्यवहार किया है। पुलिसकर्मी द्वारा की गई यह कार्यवाही पूरी तरह अस्वीकार्य, गैरकानूनी और मनमानी है। कांग्रेस नेताओं ने एसआई तलवारे और उसके वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तत्काल निलंबित करने की मांग की है। इस मामले में विधायक सचिन बिरला ने मालाकार के साथ निर्मम मारपीट की कड़ी निंदा की। बिरला ने कहा कि, पुलिसकर्मियों द्वारा प्रतिष्ठित नागरिकों से अकारण मारपीट और अपमानजनक व्यवहार जैसी घटनाओं से समाज में दहशत और भय का वातावरण उत्पन्न होता है। बिरला ने मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस नेता दीपक बैसवार, विवेक विद्यार्थी, मनीष जायसवाल, रवि प्रजापत ने भी मालाकार के साथ की गई मारपीट की कड़ी निंदा की है।

चिटफण्ड कम्पनी चलाने एवं आत्महत्या का दुष्प्रेरण करने वाले आरोपी भेजे जेल

माही की गूंज बड़वानी

न्यायायीक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री जफर खान सेंधवा ने पारित अपने आदेश मे धारा 306, 420, 120बी, 406, 408 भादवि के तहत आरोपियो राहुल पिता राजेन्द्र और भरत पिता राजेन्द्र पाटील निवासी ग्राम चाटली को जेल भेजने की कार्यवाही की है। अभियोजन की और से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन बड़वानी श्री राजमलसिंह अनारे द्वारा की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया की आरोपी रमेश पिता हेमाजी मोलवा निवासी धार ने आरकेआर चिटफण्ड कम्पनी का कार्यालय सेंधवा मे खोला था। मृतक संतोष कड़ोले को अधिक कमीशन का लालच देकर रमेश मोलवा व उसके आफिस मैनेजर राहुल पाटील, भरत पाटील तथा कोषाधिकारी रविन्द्र जगताप तथा कर्मचारी भरत पाटील व गौरव गोस्वामी ने अपनी चिटफण्ड कम्पनी का एजेन्ट बनकर लोगों के खाते खुलवाकर रूपये जमा करवाने के लिये उकसाया। मृतक संतोष कडोले उक्त आरोपीगण झासें में आ गया और उससे आरोपीगणो के कहने के अनुसार सेंधवा तथा आस-पास के निवासी व गरीब लोगों के बचत खाते इस चिटफण्ड सोसाइटी मे खुलवाये और उनके पैसे एकत्रित कर संस्था में जमा करवाये और पैसे लेकर फरार हो गये। जिसके कारण खातेदार अपना बचत का पैसा संतोष से मांगने लगे, किन्तु संस्था में लगातार ताला लगा होने एवं पदाधिकारियों के फोन बंद मिलने से संतोष कड़ोले ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी । जिस पर से मृतक के परिजनों के बयानों तथा शिकायत के आधार पर सेंधवा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

भीकनगांव पुलिस ने 6 किलों गांजा सहित 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

माही की गूंज खरगोन

भीकनगांव पुलिस द्वारा मंगलवार को 6 किलों गांजा सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनों आरोपियों को बुधवार न्यायालय में पेश किया है। भीकनगांव एसडीओपी व थाना प्रभारी ने बुधवार को थाना परिसर में प्रेसवार्ता कर यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्रसिंह चौहान के निर्देशन मे सूचना प्राप्त होने पर एएसपी जितेंद्रसिंह पंवार, एसडीओपी भीकनगांव राजाराम अवास्या के नेतृत्व में थाना पुलिस भीकनगांव द्वारा कार्यवाही की गई है।

भीकनगांव पुलिस को मंगलवार मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम ऊटखेड़ा तरफसे दो व्यक्ति मोटरसाईकल से एक प्लॉस्टिक की खाद कि थैली में अवैध रूप से गांजा भर कर जाने वाले है। मुखबीर की सूचना पर आरक्षक मांगीलाल को सूचना से अवगत करा कर तोल काटा के लिए तुलावटी व पंचानों को तलब करने के लिए कस्बा भीकनगांव रवाना किया। आरक्षक मांगीलाल के वापस आने पर मय तुलावटी व पंचानों को साथ लेकर मुखबीर द्वारा बताए हुए स्थान पर पहुंचे। यहां कुछ देर बाद दो व्यक्ति मोटर साईकल से ऊटखेड़ा तरफ से आते दिखे। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों व्यक्तियों को मोटर साईकल सहित पकड़ा।

गांजे की कुल किमत 1 लाख 20 हजार रूपए

नवलसिंह पिता जोहरिया निवासी सुल्तानपुरा, देवा पिता नहारसिंह निवासी जैतगढ बाईक पर ला रहे प्लॉस्टिक की खाद की थैली को खोला तो उसमें गांजा होना पाया। गांजे की कुल किमत 1 लाख 20 हजार रूपए होना बताई गई। आरोपियों के कब्जे से गांजा व मोटरसाईकल विधिवत जप्त कर अपराध धारा 8/20 अपराध क्रमांक 348/2020 प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।

प्रभावी पिता का प्रभाव पुत्री की बल्ले-बल्ले

संयुक्त संचालक पिता का फायदा उठाकर डॉ पुत्री कल्पना नियुक्ति के बाद से नही दे रही कोरोना काल में सेवाएं

माही की गूंज, पेटलावद

भोपाली स्तर पर किसी रिश्तेदार का पदस्थ होने पर उसका प्रभाव यहा कितना होता है यह डां. कल्पना भकोरिया ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है।

कोरोना को नियत्रंण करने के लिए जो सेवाए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जा रही है उन्ही सुविधाओ के चलते चकित्सकों को जहां कोरोना वारियर्स की संज्ञा देते हुए पुरे देश में सम्मान दिया जा रहा है। वहीं इस क्षेत्र से जुडे हुए कुछ लोगो के काम-काज के तोर-तरिकों से न सिर्फ जनता बल्की प्रशासन भी परेशान हो रहा है, ऐसा हीं एक मामला पेटलावद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर देखा जारहा है।

यह है पिता का प्रभाव

पेटलावद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर डॉ. कल्पना भकोरिया निवासी भोपाल की नियुक्ति महिला चिकित्सक के रूप में की गई थी, लेकिन डॉ. कल्पना भकोरिया के द्वारा पेटलावद स्वास्थ्य केन्द्र पर नियुक्ति दिनांक से आज तक अपनी सेवाएं नहीं दी है और लगातार पेटलावद सहित जिले का स्वास्थ्य अमला उनसे अपने पद पर कार्य करने के लिए पत्राचार कर रहा है। अस्पताल के रिकार्ड अनुसार डॉ. कल्पना भकोरिया द्वारा स्वास्थ्य विभाग के आदेश के पालन में माह अक्टूंबर 2019 में पेटलावद में चिकित्सक के पद पर ज्वाईनिंग दी थी पर ज्वाईन होने के बाद वे लगातार अपने पद पर सेवाएं देने के बजाए अनुपस्थित ही रहीं है।

बीएमओं ने लिखे कई पत्र पर प्रभाव के चलते नही हो रही कोई कार्रवाई

डॉ. भकोरिया के लगातार अनुपस्थित होने और सेवाए नहीं देने से बीएमओं डॉ. एमएल चौपड़ा द्वारा अपने वरिष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी झाबुआ को इस संदर्भ में कार्यालयिन पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 4 मई, 8 जून व 2 जुलाई को अलग-अलग पत्र जारी करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए इस संबंध में कार्रवाई के लिए पत्र जारी करते हुए उल्लेखित किया कि, डॉ. भकोरिया 9 मार्च से लगातार अपने कर्तव्य पर बीना सुचना के अनुपस्थित ही रही है, लेकिन बीएमओं के लगातार प्रयासों व पत्रोचार के बावजुद न तो जिला स्तर के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई की और ना हीं आज तक डॉ. कल्पना भकोरिया अपनी सेवाए देने के लिए पेटलावद पहुंची है।

रिकॉर्ड रजिस्टर को बनाया अपनी जागीर

बताया जारहा है डॉ. कल्पना मात्र एक यादो बार हीं पेटलावद आई है और वे जब आई तो उन्होने एक साथ अपने अस्पताल के उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए है, जब वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होने खुद को बचाने के चलते हाजरी रजिस्टर पर टीप लगाते हुए अटेंडेस रजिस्टर को अपने बाप की जागीर समझ कर छेड़-छाड भी कर दी जो स्पष्ट दिखाई दे रहीं है।

डॉक्टर के पिता है संयुक्त संचालक

डॉ. कल्पना भकोरिया को पेटलावद नियुक्त करवाना और नियुक्ति के बाद कर्तव्य पद पर लगातार गेर हाजिर रहने के बावजुद भी जिला स्वास्थ्य विभाग कोई ठोस कार्रवाई नही कर पा रहा है। इसके पिछे मुख्य कारण डॉ. भकोरिया के पिता पेटलावद सामुदायिक केन्द्र के पूर्व चिकित्सक टीडी भकोरिया जो कि वर्तमान में भोपाल स्थित स्वास्थ्य विभाग में सयुक्त संचालक के पद पर पदस्थ है। इससे स्पष्ट होता है कि इनके दबाव में जिला स्वास्थ्य विभाग कोई ठोस कार्यवाहीं नहीं कर पा रहा है। इस तरह से आदिवासी अंचल में जहां चिकित्सकों की कमी के साथ हीं संसाधनों का अभाव है, ऐसे में नियुक्ति करवाकर गैर हाजिर रहने से शासन के आदेश का उलंघन और जनता की सेवाओं में कमी का मामला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मामले में बीएमओ एमएल चोपडा ने बताया कि, हमारें द्वारा डॉ. भकोरिया की अनुपस्थिति के संबंध में समय-समय पर पत्र जारी करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सुचना दी गई है, जिसके बावजुद भी डॉ. कल्पना अपने पद पर गैर हाजिर रही है यह सही है। अब आगे की कार्यवाहीं वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों में है।

बढ़ते कोराना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन आया हरकत में

माही की गूंज, जामली, जितेन्द्र राठौर

जिले में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए प्रशासन कही न कही हरकत में आया है यह देखा जा सकता है। ग्रामीण अंचलों में भी प्रशासन द्वारा दी गई चेतावनी बिना मास्क के घूमने पर की गई चालानी कार्रवाई जामली में भी हल्का नंबर 25 के पटवारी बी.एल. बिलवाल द्वारा सौ-सौ रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। पटवारी द्वारा बताया गया कि, एसडीएम साहब के निर्देशानुसार अब ग्रामीण अंचलों में भी नियमो का पालन नहीं करने वालो एवं बिना मास्क के घूमने पर यह कार्यवाही की जा रही है। क्योंकी लोग नियमो का पालन नहीं कर पा रहे हैं जिसको देखते हुए आज ग्रामीण अंचल में पटवारी एवं कोटवार ने जामली बस स्टैण्ड चोराहे पर खड़े होकर दो पहिया ओर चार पहिया वाहनों की चालानी कार्रवाई की गई।

वहीं लोगों को घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क ओर सामाजिक दूरी का भी पालन करना चाहिए अपने घरो से तभी बाहर निकले जब जरूरी काम हो। एसडीएम साहब के दिशानिर्देशों के अनुसार पंचायत इस्तर पर चौपाल लगा कर कोराना वायरस से बचने के उपाय बताए गए कि, कैसे सोशल डिस्टेनशिंग का पालन, हाथो को साबुन से अच्छे से धोना, मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करना, सेनेटाइजर का इस्तेमाल करना, सर्दी, खासी, बुखार होने पर नजदीकी उप स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करवाए, इस मौके पर स्वास्थ विभाग, बाल विकास विभाग के कर्मचारी के साथ पंचायत सरपंच, सचिव, सहायक रोजगार, पंचायत इस्पेटर एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

नवीन पटवारियों की व्यवहारिक परीक्षा का होगा पुर्नमुंल्याकन

माही की गूंज, झाबुआ

राजस्व अनुभाग झाबुआ के समस्त नवीन पटवारियो को व्यवहारिक परीक्षा मे अनुत्तीर्ण करने का मामला प्रदेश स्तर पर तुल पकड गया है और अब आयुक्त भू-अभिलेख और बंदोबस्त म.प्र. ज्ञानेश्वर पाटिल ने हस्तक्षेप करते हुए पुर्नमुंल्यांन कर अंक निर्धारण करने के निर्देश दिये है।

उल्लेखनीय है कि, विगत दिनो झाबुआ मे पटवारियो ने म.प्र. पटवारी संघ के बेनर तले विरोध प्रदर्शित करते हुए जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा को इस संबध मे ज्ञापन सौपकर मुल्यांकन प्रक्रिया पर आक्रोष व्यक्त करते हुए विरोध प्रकट कर पुर्नमुल्यांकन करने की मांग की गई थी।

मध्यप्रदेश पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष अखिलेश मुलेवा उक्त जानकारी देते हुए बताया कि, राजस्व अनुभाग झाबुआ अन्तर्गत तहसील झाबुआ, रामा, रानापुर के समस्त नवीन पटवारीयो को तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी ने व्यवहारिक परीक्षा मे अनुसूचित जनजाति के लिये उर्त्तीणांक से कम अंक देकर सभी नवीन पटवारियो को अनुतीर्ण कर दिया था, जबकि सेंद्वातिक परीक्षा मे अनुभाग के समस्त पटवाारी अच्छे अंको के साथ उतीर्ण हुए और प्रदेश की प्रावीण्य सूचि मे स्थान अर्जित किया किन्तु व्यवहारिक परीक्षा मे इन सभी पटवारियो को मात्र 35 से 36 अंक देकर अनुतीर्ण कर दिया गया। इस परिणाम से पटवारियो मे रोष व्याप्त हो गया और विरोध स्वरूप पटवारियो ने 13 जुलाई को जिला कलेक्टर प्रबल सिपाहा को ज्ञापन सौपकर पुर्नमुल्यांकन करने की मांग की गई थी तथा प्रदेश स्तर पर आयुक्त भू-अभिलेख और बदोबस्त म.प्र. तथा प्रमुख सचिव राजस्व के संज्ञान मे भी लाया गया। पटवारी संघ के इस विरोध प्रर्दशन और ज्ञापन सौपने पर आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त मध्यप्रदेश ज्ञानेश्वर पाटिल ने मंगलवार को विडीयो कांन्फ्रेस मे निर्देश देकर कहा कि, व्यवहारिक परीक्षा मे अनुर्तीण समस्त पटवारियो के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण फाईल का पुर्नमुल्यांकन किया जावे तथा प्रकरणवार अंको का विभाजन कर पृथक-पृथक गणना कर पुनः अंक निर्धारण कर जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजे जाए।

कोरोना की नगर में हुई आमद, वार्ड नम्बर 6 में सामने आए दो मामले

माही की गूंज, पेटलावद

पेटलावद तहसील में कोरोना के मामले कम हैं, नगर में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नही मिला लेकिन रविवार को नगर के लिए बुरी खबर आई। पेटलावद वार्ड क्रमांक 6 में साई मंदिर के समीप एक 52 वर्षीय व्यक्ति जो पेशे से ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके साथ नगर में कोरोना के प्रमाणित आंकड़े की शुरुआत हुई है, इससे पहले नगर के इसी वार्ड ओर साई मंदिर के सामने एक महिला कोरोना संकृमित पाई गई थी, लेकिन उसका इलाज धार जिले में चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब मरीज को झाबुआ जिला चिकित्सालय भेजा गया और संपर्क में आये 03 लोगो के सेम्पल लिए गए जिसकी जांच में कोरोना संकृमित की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई

खानापूर्ति के लिए बनाया गया कन्टेन्टमेंट झोन, आसानी से आ जा रहे थे लोग, युवक का हजार रुपये का चालान फाड़ा

कन्टेन्टमेंट झोन से निकल रहे लोगो पर कार्यवाही करते एसडीएम गर्ग ओर राजस्व अमला

जिससे नगर में केश की संख्या दो हो गई हैं।

खानापूर्ति के लिए बना कन्टेन्टमेंट झोन

नगर में रविवार को कोरोना के मामले सामने आने के बाद में आनन-फानन में प्रशासन द्वारा मरीज को झाबुआ जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन में भर्ती किया गया। पेटलावद के जिस एरिया में मरीज निवास करता था, उस एरिया को प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की कई लेकिन अन्य जगहों की मुकाबले यहाँ मात्र टेंट मात्र लगा कर इतिश्री कर ना तो पुलिस प्रशासन की ओर से न ही प्रशासन की और किसी कर्मचारी या अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कंटेन्टमेंट झोन से लगातार लोगो का बहार आना-जाना हो रहा है। मीडिया में मामला आने के बाद प्रशासन ने कन्टेन्टमेंट झोन से निकल रहे युवक को रंगे हाथ धरा ओर एक हजार रुपये की दंड रसीद बनाकर फिर से कंटेन्टमेंट एरिए में छोड़ा गया जिसके बाद फिर से बॉस-बल्ली से पूरे एरिये को सील किया गया।

लोग हो रहे परेशान

जो लोग कंटेनमेंट एरिया में रह रहे हैं उनके लिए जरूरी समान की सुविधा को लेकर कोई व्यवस्था होती नही दिखी, जिससे लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगो को घरो की छत पर आकर और मोबाइल के जरिये जरूरी सामान पहुचाने के लिए अपने मिलने वालों से संपर्क करना पड़ रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के पास जाँच किट की कमी ?

शुरू-शुरू में कोरोना के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकृमित के संपर्क में आये लोगो के साथ पड़ोसियो के भी सेम्पल जाँच हेतु लिये जाते है, लेकिन अब देखा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की जांच का दायरा केवल परिवार तक सीमित रह गया है। यदि बहारी दबाव नही हो तो स्वास्थ्य विभाग संक्रमित परिवार के सदस्यों के अलावा किसी की जांच नही कर रहा, बामनिया के बाद पेटलावद में भी जांच के लिए गए सेम्पल की संख्या बहुत कम रही और केवल 3 लोगो के सेम्पल लिए गये जिसमे से एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी ट्रेवल हिस्ट्री तक कि तलाश नही की गई, इसके पीछे के कारण जो सामने आ रहे हैं उसमें स्वास्थ्य विभाग के पास जाँच किट की कमी होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि, जांच किट की कमी नही है, लगातार जाँच सेम्पल में हो रही कमी से सवाल खड़े हो रहे हैं।

रक्षाबंधन से पहले इस बार बाजारों से रौनक गायब...

माही की गूंज कुन्दनपुर, कृष्णपाल सिंह ठाकुर

भाई बहन के पवित्र प्रेम व विश्वास के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व को मात्र 4 दिन शेष है, लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते अभी तक राखी की चमक कुंदनपुर व ग्रामीण इलाको में नहीं दिखाई दे पा रही है। कोरोना वायरस के कारण त्यौहार भी खत्म होते नजर आ रहे हैं।

वायरस के कारण ग्रामीण क्षेत्र कुंदनपुर में बाजारों की रौनक कम हो रही है।

मानसून के बाद देश में त्योहारों को सीजन शुरु हो जाता है और रक्षाबंधन के बाद साल के अंत तक कोई ना कोई त्यौहार लगातार जारी रहता है। बाजार की भाषा में कहें तो यह समय त्यौहारी सीजन होता है जिसमें व्यापारियों को एक बड़ा मुनाफा कमाने को मिलता है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हालात अच्छे नहीं है बाजारों में जो रौनक हर साल शुरु होती थी वह नजर नहीं आ रही है।

बायपास पर रोड को बचाने के लिए लगाया गेट

माही की गूंज, रायपुरिया

पेटलावद-रायपुरिया मार्ग से निकलने वाले वाहन नगर में होकर नही निकले इसके लिए रायपुरिया के बाहर से पुलिस थाने के पीछे से एक बायपास रोड़ बनाया गया ताकि ऐसे वाहन जिनको रायपुरिया नगर या राजगढ़ की और नही जाना हो वो इस बायपास से सीधे झाबुआ मार्ग ओर झाबुआ मार्ग से सीधे पेटलावद मार्ग पर निकल सके, लेकिन ये व्यवस्था रोड ठेकेदार को भारी पड़ गई और मात्र 15 टन पास रोड से 40 से 50 टन क्षमता से अधिक लोडेड वाहन इस वैकल्पिक मार्ग से गुजरने लग गए, जिससे मार्ग की हालत थोड़े-थोड़े दिनों में ही खस्ता हो जाती हैं और ठेकेदार को मार्ग की रिपेयरिंग करना पड़ती हैं। भारी वाहनों की भेंट चढ़े उक्त मार्ग को लोक निर्माण विभाग, ठेकेदार के घटिया निर्माण और टेंडर की शर्तों अनुसार ठेकेदार की जिम्मेदारी बताकर बार-बार रिपेयरिंग के नोटिस थमा रहा है जिससे परेशान रोड ठेकेदार ने बायपास रोड के दोनों और भारी एंगल का लगभग 12 फिट ऊँचा शेड खड़ा कर दिया जिससे उक्त

लोक निर्माण विभाग, ठेकेदार को थमा रहा हैं बार-बार रिपेयरिंग के नोटिस

मार्ग से भारी वाहन नही गुजर सके।

बायपास मार्ग बंद होने से गांव में होकर गुजर रहे भारी वाहन

छोटे व्हीकल से लेकर ट्रक, आइसर आदि आज भी बायपास रोड से आसानी से निकल रहे हैं, लेकिन बड़े ट्राले, गेस टैंकर सहित अत्यधिक ऊंचे और भारी वाहन इस मार्ग से गुजरना बन्द हो गए, जिससे बड़े और भारी वाहन अब ग्राम कें मुख्य मार्ग से निकल रहे हैं ओर ग्राम में भीड़-भाड़ होने से दुर्घटना का भय बना रहता है, जिससे कई लोग बायपास रोड पर लगे इंगल के शेड को निकालने की मांग कर रहे है। मामले में रोड के ठेकेदार का साफकहना है कि, विभाग द्वारा बार-बार रिपेयरिंग के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, रोड मात्र 15 टन पास ही हैं और इस पर से 50 टन से भी अधिक लोडेड वाहन गुजर रहे है जिससे बार-बार रोड पर रिपेयरिंग करना पड़ रही हैं और हमारा नुकसान हो रहा है, ठेकेदार जीवन पाटीदार का कहना है कि, रोड के मेंटेनेंस का जिम्मा 2022 तक हमारा हैं ऐसे में अगर इस रोड से भारी वाहन निकलते रहे है तो हमारी नुकसानी का वहन कोन करेगा। यदि लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वयं रोड की जबाबदारी लेता हैं तो, हम किसी प्रकार के वाहनों को नही रोकेंगे और वेसे भी जीन वाहनों को इस मार्ग से निकलना हैं उनको किसी तरह की परेशानी नही आ रही हैं और किसी प्रकार की रोक नही लगाई गई है, पेटलावद, बामनिया सहित सभी गाँव से वाहन नगर में से ही निकल रहे हैं।

टोल बचाने के लिए आते हैं भारी वाहन

पूरे मामले को थांदला-बदनावर मार्ग पर लगे ईगलदीप के बीच लगे टोल से जोड़कर भी देखा जा रहा है, टोल बचाने के लिए भारी वाहन चालक अपने वाहन से बदनावर से आते हुए टोल से गुजरने की बजाए रायपुरिया रोड पर डाल देते हैं। वही झाबुआ की और से आने वाले भारी वाहन चालक भी थांदला होकर बदनावर जाने की बजाय रायपुरिया से पेटलावद होकर बदनावर रोड पकड़ कर निकल जाते है। इससे पहले भी भारी वाहनों के कारण रायपुरिया-झाबुआ मार्ग पर कई पुल डह चुके है ओर कई लोग मौत के घाट उतर चुके हैं, बावजूद इसके इस रोड से आज भी भारी वाहन बस्तुर गुजर रहे हैं, मामले लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात करने का प्रयास भी किया गया लेकिन जबाबदारो ने फोन नही उठाया।

दुर्घटना या हत्या: आखिर क्या हुआ था गोपाल के साथ ?

एक माह पहले दुर्घटना में हुई गोपाल की मौत पर संदेह, जयस ने सोपा ज्ञापन

माही की गूंज, पेटलावद

1 जुलाई को रात्रि में पेटलावद-रायपुरिया मार्ग पर मातापाड़ा के युवक गोपाल कटारा की दुर्घटना में हुई मौत को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। दुर्घटना के बाद से गोपाल की मौत को लेकर आम चर्चा में कई तरह की बाते सामने आ रही थी जिसमे मामले को हत्या से भी जोड़ कर देखा जा रहा था। दुर्घटना स्थल को देखने के बाद हर किसी के मन में संदेह उतपन्न हो रहा था, लेकिन पुलिस मामले को दुर्घटना ही मान कर चल रही है। विगत दिनों मामले में जयस ने पुलिस अधीक्षक झाबुआ के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को भी देकर गोपाल कटारा की मौत को पूरी तरह से संदेस्पद बताते हुए मामले में जांच की मांग की हैं।

छः बिंदुओं को लेकर सौपा ज्ञापन

गोपाल कटारा जयस का सक्रिय सदस्य था और सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता था, गोपाल की मौत के बाद जयस के सहयोगी साथी घटना स्थल पर गए जिसे देखने के बाद गोपाल की दुर्घटना में हुई मौत को लेकर आश्वस्त नही हुए। जयस संगठन ने पुलिस अधीक्षक के नाम सौपे छः बिंदुओं को आधार बना कर ज्ञापन सौपा ,जयस संगठन ने ज्ञापन में बताया कि गोपाल का शव उसके वाहन से काफी दूर लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर मिला, दुर्घटना की जानकारी के बाद तत्काल वाहन दुर्घटना स्थल से हटा लिया गया, गोपाल का पेंट का बेल्ट उसके शव से अलग निकला हुआ मिला और उसके गले मे डले गमछे में खून का एक भी दाग नही लगा, जबकि गोपाल का काफी सारा खून बह चुका था, जयस का कहना है कि, इतनी बुरी तरह से चोट लगने के बाद भी गोपाल के शरीर से कही रगड़ के निशान नही है। गोपाल के साथियों का कहना है कि, गोपाल उसकी मौत से पूर्व कई दिनों से परेशान था और उसका एक व्यक्ति से विवाद भी चल रहा था और उसे देख लेने की धमकी भी दी जा रही थी, जिसकी जानकारी कई साथियों को खुद गोपाल ने दी थी, जयस ने गोपाल की मौत पर सवाल खड़े करते हुए दुर्धटना वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर मामले के खुलासे की मांग की हैं।

गूंज की पड़ताल में भी मामला संदिग्ध

दुर्घटना के बाद गूंज टीम ने भी दुर्घटना स्थल का दौरा किया था, जिसमे मामला पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रहा था। म्रतक गोपाल का वाहन उसके शव से लगभग 4 सौ से 5 सौ मीटर दुर मिला, जबकि बताया जा रहा था कि, दुर्घटना दो दुपहिया वाहनों के बीच भीडत से हुई है। घटना के बाद गोपाल का वाहन पुलिस ने उठाकर थाने पर ले जाने की बजाए एक दुकान के पीछे छुपा कर रख दिया था, वाहन के पास एक बाइक का हिस्सा टूटा हुआ पडा था जो न तो गोपाल की बाइक का था न ही जिससे वाहन की टक्कर बताई जा रही उस मोटर साइकिल का, जिस मामले में कई ऐसे पेच हैं जिससे गोपाल की मौत के पीछे सवाल खड़े हो रहे है।

अहिंसा के पुजारी की कारस्तानी आई सामने तो पंचों को धमकाया व मीडिया कर्मी पर भी बनाया दबाव

मामला : विलुप्त प्रजापति श्याम चिड़िया के घोसले को फेंकने से चिड़ियाओ की हुई मौत का

माही की गूंज झाबुआ

ऐसे कई मामले होते हैं जो देखने व सुनने में काफी छोटे व सामान्य लगते हैं, परंतु उन मामलों में भी ऐसे मामले होते हैं जो कितने बड़े होते हैं वह परिकल्पना मात्र से महसूस कर सकते हैं।

ऐसा ही एक मामला पेटलावद में नदी किनारे श्याम चिड़िया के साथ उनके घोसले को फेंकने का सामने आया जो देखने और सुनने में मामला छोटा प्रतित होता है, परंतु जब इस मामले की परिकल्पना करें तो यह मामला कितना बड़ा है यह अपने-अपने विचारों पर निर्भर करता है।

प्राप्त जानकारी अनुसार सोमवार शाम को नगर के वार्ड क्रमांक 12, सुभाष मार्ग, शनि मंदिर के पीछे, पम्पावती नदी के किनारे एवं एक घर के आस-पास विलुप्त प्रजाति की श्याम चिड़ियाओ का बड़ा झूंड घूम-घूमकर शौर करने लगी, काफी देर तक लोगों को समझ में ही नही आया की आखिर शांत स्वभाव की चिड़िया इतनी उग्र क्यों है। धीरे-धीरे लोगों की भीड़ हो गई और देखा चिड़िया के घोसले को बड़ी संख्या में पम्पावती नदी के किनारे बिखरे पड़े घोंसलो के साथ बड़ी संख्या में चिड़िया के बच्चों को भी देखा गया, जिसमें से कई बच्चे मर चुके थे तो कई बच्चे कुत्ते, कवे व कई जानवरों का शिकार भी बन गए थे। उक्त दृश्य देख वार्ड वासियों ने मामले की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी।

मौके पर सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और तुरंत कार्रवाई करते हुए जो चिड़िया के बच्चे जीवित थे, उन्हें सुरक्षित किया व उक्त चिड़िया के घोसले को फेंक कर अमानवीय व कुकृत्य करने वाले की जानकारी ली तो, लोगों ने बताया वार्ड क्रमांक 12 के ही निवासी राजेश पिता आनंदीलाल वोरा जिसके घर के पीछे वाले हिस्से में बड़ी संख्या में इन चिड़ियों के झुंड ने अपना रैन बसेरा बना रखा था और घर की साफ-सफाई के नाम पर इन बेजुबान चिड़िया के घोसलों को उनके बच्चों सहित नदी किनारे फेंक दिया।

वन विभाग ने बनाया पंचनामा 50 बच्चे मिले मृत 45 को किया सुरक्षित

वन विभाग को मिली जानकारी पर राजेश वोरा की तलाश की तो वह उसके घर पर ही मिला और पूरी पुष्टि के बाद वन विभाग के अधिकारी ने राजेश वोरा की उपस्थिति में पंचनामा बनाया।

पंचों की उपस्थिति में फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी ने घोसले एवं मतृ चिड़ियाओं को जप्त कर बनाया मौका पंचनामा

पंचनामे में पंपावती नदी के किनारे लगभग 170 घोंसले श्याम चिड़िया के फेंके हुए मिले जीवित बच्चे 45 जिन्हें सुरक्षित किया गया, वही श्याम चिड़ियाए उड़ती हुई बच्चो की तलाश में नजर आई, साथ ही 50 बच्चे मृत मिले वही कौवे, कुत्ते वह अन्य जानवर भी चिड़िया के बच्चों को खा गए। बताया जा रहा है सौ से अधिक चिडिया के बच्चे की मोत घोसले फेकने से हुई।

वहीं पंचों द्वारा बताया गया राजेश पिता आनंदीलाल वोरा के यहां श्याम चिड़िया के घोसले थे उनको उठाकर उनके द्वारा फेंका गया तलाश की गई तो, राजेश वोरा घर पर ही मिला और उसके समक्ष ही पंचनामा बनाया। पंचनामा में पुष्टि की गई कि, राजेश वोरा द्वारा ही उक्त 170 के करीब चिड़िया के घोसले को फेंका गया, उक्त पंचनामें पर राजेश वोरा ने भी अपने हस्ताक्षर कर उक्त मामले को स्वीकार किया।

मामला उजागर होने के बाद वोरा परिवार आया हरकत में

उक्त वन विभाग की मौके पर कार्यवाही के बाद मामला न्यूज पोर्टल की वेबसाइट पर सार्वजनिक हुआ और जो वोरा परिवार अहिंसा परमो धर्म को मानते हैं, वह अपने इस अमानवीय कृत्य को बहुत छोटा व आम मान रहे थे। वह मामले के उजागर होने के बाद जैसे ही उनके घर एवं परिवार के सदस्यों पर जैन समाज के साथ कई इष्ट मित्रों जो इस घटना को बड़ा मान अहिंसा परमोधर्म का हवाला देकर राजेश एक जैन समाज का सदस्य होकर उसने ऐसा क्रत्य किया जो निंदनीय है का अहसास करवाया। जिसके बाद पूरा परिवार ऐसा बोखलाया की वार्ड क्र. 12 के पार्षद अशोक शर्मा के साथ पंच के रूप में जिन्होने भी पंचनामे में हस्ताक्षर किये उन्हें फोन कर अनर्गल बाते की व अशोक शर्मा को धमकाने का प्रयास किया। जिस पर श्री शर्मा ने वोरा परीवार के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु रिपार्ट दर्ज करवाई।

वही अन्य न्यूज पोर्टल के साथ माही की गूंज न्यूज पोर्टल में लगी न्यूज को डिलीट करवाने हेतु वोरा परिवार की रतलाम निवासी महिला ने आधी रात के बाद तक फोन किए। वहीं रात्रि में फोन अटेन्ड नही होने के बाद भोर होते ही हमारे पेटलावद प्रतिनिधी को फोन कर जैन समाज का बताकर व अहिंसा परमोधर्म का हवाला देकर अपने-आप को सही साबित कर न्यूज को डिजिट करने का दबाव बनाया। परन्तु माही की गूंज ने वन विभाग की मोके पर पंचनामे के साथ की गई कार्यवाही अनुसार समाचार प्रकाशित किया है। वह डिलिट नही होगा स्पष्ट कह दिया।

"गुंज पड़ताल"

गुंज के सूत्रोनुसार महिला द्वारा रात्रि से लेकर दूसरे दिन तक पंचगणो एवं मीडियाकर्मी को धमकाने एवं दबाव बनाने की पूरी कहानी जानी तो, पता चला वोरा रिश्तेदार के एक प्रभावी सदस्य से पेटलावद के एक वन विभाग के अधिकारी को मामले को रफा-दफा करने हेतु फोन लगाया गया तो, अधिकारी ने न्यूज पोर्टलो पर समाचार प्रकाशित होकर मामला सार्वजनिक हो गया है, इसलिए मामला कैसे रफा-दफा होगा? जिस पर प्रभावी व्यक्ति ने अधिकारी को आश्वस्त किया कि, अगर न्यूज पोर्टल से समाचार डिलीट हो जाए और जिन्होंने पंचनामें पर हस्ताक्षर किए वह कोई आपत्ति ना ले तो मामले को एक बार रफा-दफा कर सकते हैं। गूंज सूत्रों के अनुसार अधिकारी के उक्त आश्वासन के बाद

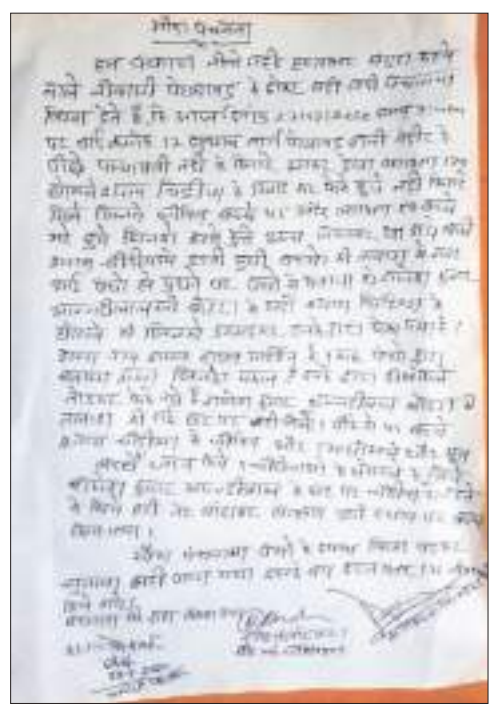

वोरा परिवार की महिला ने जो शिक्षित होकर कानून की ज्ञाता भी हे ने, न्यूज को डिलीट करवाने का प्रयास किया पर माही की गूंज किसी भी स्थिति में प्रकाशित समाचार को डिलीट नहीं करता है, इसलिए उनकी दाल यहां नहीं गली वही पंचो पर भी ऐसा दबाव बनाया कि, वह डर के मारे फारेस्ट विभाग को कार्रवाई हेतु दबाव नहीं बनावे।

मामले में वन विभाग के अधिकारी हरिराम चरपोटा से जानकारी ली तो बताया मामले की जांच चल रही है, 7 मृत चिड़िया का पोस्टमार्टम करवाया है, अभी मामला दर्ज नहीं हुआ है, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जिसके घर से चिड़िया के घोसले फेंके गए हैं उन पर कार्रवाई होगी। अब देखना है यह की फॉरेस्ट विभाग उक्त मामले में कुछ कार्रवाई करता है या प्रभावी व्यक्ति के प्रभाव में आकर मामले को रफा-दफा।

सर्पदंश से एक मौत

माही की गूंज, रायपुरिया/तारखेड़ी

सोमवार दोपहर करीब 3 बजे के समय खेत में कार्य कर रहे किसान राजू पिता मांगु को अचानक से पीछे से सांप ने काट लिया। युवक अपने परिवार वालो के साथ खेत पर कार्य कर रहा था तभी युवक को चक्कर आने लगे तो युवक विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे सोया था, साथ मे काम कर रही युवक की पत्नी ने अपने पति के मुंह में कुछ सफेद पानी के झांक निकलते देखे तो महिला के होश उड़ गए, महिला ने आवाज लगाकर सभी परिजनो को बुलाया सभी मौके पर पहुंचे, युवक को हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि राजू ने प्राण त्याग दिए।

बामनिया का कंटेनमेंट खुला पेटलवाद मार्ग हुआ चालु

माही की गूंज बामनीया

बामनिया-पेटलावद रोड का कंटेनमेंट और रतलाम रोड का बफर झोन आखिर 21 दिन बाद खुल ही गया। रहवासियों ने राहत की सांस ली, आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रशासन ने राहत दी है, वही व्यापारियों को सख्ती से सुरक्षा का पालन करने के आदेश दिए है, व कहा कि, दुकान पर सोशल डिस्टेंसिग का पालन हो व मास्क का उपयोग जरूरी है। वही उक्त कंटेनमेंट खुलने से पेटलावद जाने का मुख्य मार्ग भी चालु हो गया।

बंदूक के दम पर अपहरण कर ले गया कर्नाटक नशीली दवाई दे कर करता रहा बलात्कार

पुलिस न एफआईआर दर्ज कर रही न युवती का परिक्षण करवा रही और सलाह दे रही कि, बलात्कारीयो से भांजगडी कर समझोता कर लो

माही की गूंज, बामनिया गौरव मंडारी

मुख्यमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रदेश को दे रहे है वही बामनिया के पास गोदड़िया की एक 21 वर्षीय करिश्मा को पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे से दिन दहाड़े 4 युवक अपहरण कर के ले गए।

बदला हुआ नाम करिश्मा करिश्मा ने गूंज प्रतिनिधि से बात करने पर बताया कि, 21 जून को दिन में वो अपनी बहन के घर बड़ी गेहंड़ी जा रही थी, वही रास्ते मे बुलेरो जीप आ कर रुकी जीप से आरोपित दिनेश पिता चम्पालाल मालवीय ग्राम बोदला चौकी अमझेरा थाना सरदारपुर जिला धार व उसके साथ 3 साथी आरोपी जीप से उतरे दिनेश ने करिश्मा को साथ मे चलने को कहा, करिश्मा के मना करने पर बंदूक निकाल कर डरा धमकाकर जीप में बिठाया, बोला अगर जीप में नही बैठी तो तुझे जान से मार देंगे। जीप में बैठने के बाद उसे नशीली दवाई सुंघाई गई, जिससे वो बेहोश हो गई, कई दिनों तक नशीली दवाई दी गई ओर दुष्कर्म किया। करिश्मा ने बताया कि, उसे 15 दिन तक कोई होश नही था, जब उसे होश आया तो उसे बताया गया कि, वो कर्नाटक के किसी गाँव में है, जब उसने अपने माता-पिता के पास जाने की जिद की तो उसके साथ बहुत मारपीट की व उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया गया, मौका पाकर करिश्मा ने उसके घर वालो को फोन लगाया और बताया कि, अपने ही गांव की एक महिला सीता बाई पति सोहन मईड़ा निवासी गोदड़िया के यहाँ आरोपित दिनेश का आना-जाना लगा रहता था, दिनेश भोपा-बडवाई करता था, कितनी ही बार सीता बाई ने करिश्मा को आरोपित

दिनेश से शादी की बात कही थी, उस पर करिश्मा ने मना बोल कर की मेरी सगाई मेरे माता-पिता ने कर दी है, अपहरण वाले दिन भी सीता बाई ने करिश्मा को खेत पर काम करने के लिए बुलाया था, करिश्मा के माता-पिता ने 30 जून बामनिया पुलिस चौकी पर सीता बाई के खिलाफ आवेदन दिया था, जिसमे पुलिस ने जाँच करना बताया।

आरोपित दिनेश करिश्मा को जादू टोने करने वाले एक बाबा के पास भी लेकर गया था, आरोपित दिनेश को जब पता चला कि, करिश्मा के माता-पिता ने सीता बाई के नाम का आवेदन पुलिस चौकी में दिया है तो दिनेश ने करिश्मा को और उसके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी व उसे जीप में कर्नाटक से लेकर 5 दिन में मध्यप्रदेश की सिमा में आ गए आरोपितों ने डर के मारे करिश्मा को रास्ते मे ही उतार दिया व भाग गए। करिश्मा किसी की मदद से घर वालो को फोन लगाया व घर वाले उसे लेने आए, करिश्मा के माता-पिता ने ग्राम बोदला के अमझेरा चौकी पर आरोपितों के नाम का आवेदन भी दिया है।

करिश्मा व उसके माता-पिता ने आरोप लगाया है कि, वे 2 बार बामनिया चौकी पर करिश्मा को ले कर गये पर चौकी प्रभारी ने एफआईआर दर्ज नही की व न ही ठोस कोई कार्यवाही। करिश्मा ने बताया चौकी प्रभारी बोलते है तुम्हारे आदिवासी में भांजगडी कर फैसला कर लो, जिसके बाद उन्हें पेटलावाद थाने जाना पडा। वहा से उन्हें वापस बामनिया चौकी भेजा गया, जहाँ बयान लिए पर कोई कार्रवाई बलात्कार करने वाले के विरूद्ध नही की, जिसके बाद करिश्मा के पिता ने एसपी को शिकायत की, करिश्मा यही बोलते हुए रोने लगी कि मुझे न्याय मिलेगा या नही।

इस मामले में बामनिया चौकी प्रभारी मोहनसिंह सोलंकी से बात करने पर उन्होंने बताया कि, आवेदन आया है जाँच चल रही है जल्द ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई टाइटल कोड नंबर- एमपीएचआईएन-76422